mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-02 अंक-177 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

मनेन्द्रगढ़
28 जून 2026 रविवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

: ब्रीफ बॉक्स :

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर धीरेंद्र शास्त्री भावुक हुए

बोले- रावण तो ये भी हैं, बस रूप बदला

अयोध्या,एजेंसी। अयोध्या राम मंदिर चोरी पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री भावुक हो गए। इंडोनेशिया के जकार्ता में शुक्रवार को कहा- रावण तो ये भी हैं बस रूप बदल गए हैं। रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी। राम मंदिर के दानपात्र से लाखों-करोड़ों लोगों की श्रद्धा और भरोसा चोरी हुआ। हमें खबर मिली है कि FIR हुई है। अभी और जांच हो। पक्का है और पकड़े जाएंगे।

उन्होंने कहा- सच तो सच है, जिसको बुरा लगता है उसे लगे। रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि उसका परिवार नाश हो गया। चढ़ावा चोरी करने वाले सरकारी दंड तो पाएंगे ही ही, भगवान भी महादंड देंगे। जेल सूत्रों ने अनुसार, रामशंकर यादव उर्फ टिन्न समेत 8 आरोपियों को फैजाबाद जेल में पहली रात नींद नहीं आई। सभी करवटें बदलते रहे।

पीएम मोदी सेशेल्स रवाना 11 साल में दूसरा दौरा

राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे

विक्टोरिया,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक तीन दिन सेशेल्स दौरे के लिए शनिवार सुबह 8.50 बजे रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं।

मोदी सेशेल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर होने वाली परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी हिस्सा लेंगे।

मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सेशेल्स की राष्ट्रीय विधानसभा को भी संबोधित करेंगे। सेशेल्स में रहने वाले भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे।

मोदी का पिछले 11 साल में यह दूसरा सेशेल्स का दौरा है। इससे पहले उन्होंने साल 2015 में इस द्वीप देश की यात्रा की थी। सेशेल्स की आबादी 1.35 लाख है। इसमें से 12 हजार के करीब लोग भारतीय मूल के हैं। यह करीब 8 से 9% हिस्सा है।

सोनिया बोलीं: गाजा में बच्चों को खत्म करने की कोशिश

भारत अकेला जिसने चुप्पी साधी

» दुनिया इजराइल से दूर जा रही, भारत पास

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर मोदी सरकार के स्टैंड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, 'संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट बताती है कि इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से बच्चों को निशाना बना रहा है। इतनी गंभीर रिपोर्ट आने के बाद भी मोदी सरकार चुप है।'

सोनिया ने लिखा कि इस आयोग की अगुआई अब भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस. मुरलीधर कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में जारी 94 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की कार्रवाई का मकसद गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करना है और इसके लिए बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है।

सोनिया बोलीं- भारत अकेली आवाज, जिसने चुप्पी साधी: सोनिया गांधी ने कहा कि जब पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय गाजा में हुई तबाही को गंभीरता से देख रहा है, तब भारत सरकार अकेली ऐसी आवाज बन गई है, जिसने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि जस्टिस एस. मुरलीधर की रिपोर्ट पर भी मोदी सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने अपने लेख में जस्टिस मुरलीधर के दिल्ली हाईकोर्ट से तबादले का भी जिक्र किया।

उन्होंने लिखा कि उनका तबादला उस समय हुआ था, जब उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों से पहले BJP नेताओं के कथित भड़काऊ बयानों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला:

कब्जा मिलने के बाद भी बिल्डर से मुआवजे की मांग कर सकते हैं घर खरीदार

नई दिल्ली,एजेंसी। फ्लैट का कब्जा लेने के बाद भी घर खरीदार सर्विस में कमी के लिए रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदार फ्लैट का कब्जा लेने के बाद भी कब्जा मिलने में हुई देरी के लिए मुआवजा पाने के लिए डेवलपर्स के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें कहा गया था कि फ्लैट का कब्जा लेने के बाद घर खरीदार कंज्यूमर नहीं रह जाता और देरी के लिए मुआवजा नहीं मांग सकता।

कंज्यूमर फोरम जाने से नहीं रोका जा सकता: अदालत ने यह भी कहा कि घर खरीदार और रियल एस्टेट कंपनी के बीच हुए एग्रीमेंट में मौजूद आर्बिट्रेशन क्लॉज (मध्यस्थता की शर्त) खरीदार को अपनी शिकायतें लेकर कंज्यूमर फोरम में जाने से नहीं रोक सकता।

एनसीआर के द्वारका में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट का कब्जा मिलने के बाईस साल बाद जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने फ्लैट सौंपने में हुई देरी के लिए मुआवजा मांगने की खरीदार की याचिका को मंजूरी दे दी। बेंच ने कहा कि एनसीडीआरसी का तर्क सही नहीं ठहराया जा सकता।

पीठ ने क्या कहा? बेंच ने कहा, 'अपीलकर्ता की शिकायत सिर्फ कब्जा पाने के बारे में नहीं थी। उसकी शिकायत यह थी कि फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी हुई थी और वह इस देरी के लिए मुआवजा पाने का हकदार था। कब्जा मिलने में देरी के लिए मुआवजे का दावा असल में कब्जा मिलने से पहले की अवधि से जुड़ा होता है। बाद में कब्जा मिल जाने से देरी के लिए मुआवजे के दावे पर फैसला पाने का अलॉटी (आवंटी) का अधिकार अपने-आप खत्म नहीं हो जाता।' बेंच ने घर खरीदार की ओर से जिला उपभोक्ता फोरम में 2005 में दायर शिकायत को फिर से शुरू किया और फोरम से कहा कि वह एक साल के भीतर यह तय करे कि क्या इसमें कोई देरी हुई थी।

एक साल में मतदाता सूची से कटे करीब छह करोड़ नाम

» अभी कई प्रदेशों में चल रहा एसआईआर

नई दिल्ली,एजेंसी। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू हुए एक वर्ष पूरा हो गया है। इसके तहत अब तक लगभग छह करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं।

19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अभी यह प्रक्रिया चल रही है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष 24 जून को बिहार विधानसभा चुनावों से पहले हुई थी।

बिहार के एसआइआर में मतदाता सूचियों से लगभग 65 लाख नाम हटाए गए थे। इस कारण चुनाव आयोग पर नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने के आरोप लगे थे, लेकिन इस वर्ष मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था।

पिछले वर्ष 27 अक्टूबर को घोषित एसआईआर के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा समेत 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों से 10.2 प्रतिशत नाम हटाए गए।

यहां एसआईआर से पहले कुल मतदाता 50.99 करोड़ से अधिक थे, जो अब 45.81 करोड़ रह गए हैं। यानी लगभग 5.18 करोड़ कम हुए हैं।

महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक, एग्जाम आज होना था

● सरकार ने परीक्षा रद्द की, पेपर ठाणे से बरामद ● सरकारी टीचर्स के लिए ये परीक्षा जरूरी

मुंबई,एजेंसी। महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का क्वेश्चन पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। एग्जाम रविवार को होना था। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल (MSEC) ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, क्वेश्चन पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया और जब्त पेपर को वेरिफाई कराया गया

पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि संख्या नहीं बताई है। यह कार्रवाई एग्जाम के 24 घंटे पहले की गई। परीक्षा में 4.28 लाख ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं, उनके लिए भी TET कंपलसरी है।

इससे पहले NEET और यूपी पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हुआ: पिछले 5 साल में देश में 9 बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इनमें राजस्थान रीट (REET), यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और हाल ही में मई 2026 में हुए नीट यूजी (NEET-UG) जैसे बड़े एग्जाम्स शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट बोला- शिक्षकों को अश्वश्र पास करना ही होगा...

सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को स्पष्ट किया कि स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने अश्वश्र पास करने की समयसीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा, बिना अश्वश्र योग्यता वाले शिक्षक सेवा में बने रहे तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर पड़ेगा।

वेनेजुएला में फिर 4.9 तीव्रता का भूकंप, अबतक 920 मौतें

» लोग खुद मलबा हटाकर अपनों को तलाश रहे

करीब 3300 घायल, 51 हजार लापता

कराकस, वेनेजुएला, एजेंसी। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 25 जून को आए दो भूकंप के बाद स्थानीय समयानुसार शुक्रवार दोपहर को एक और भूकंप आया। देश के उत्तरी तट के पास आए इस भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। रॉयटर्स के मुताबिक, राजधानी कराकास और माराके में भी झटके महसूस किए गए।

इधर, पिछले भूकंप के तीन दिन बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। 3360 से ज्यादा घायल हैं, जबकि 51,700 से ज्यादा लोग लापता हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अब तक 243 लोगों को जिंदा बचाया गया है। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। कई इलाकों में राहत टीमों की कमी के कारण लोग परिजन को ढूंढ़ने के लिए खुद मलबा हटा रहे हैं। कई परिवार हथौड़ों और दूसरे औजारों से इमारतों का मलबा हटाकर अपने परिजन की तलाश कर रहे हैं।

राष्ट्रपति रोड्रिगेज बोली- भूकंप के बाद ट्रम्प ने मदद का भरोसा दिया: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बताया कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और विदेश मंत्री मार्को रुबियो का फोन आया था। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने इस मुश्किल समय में वेनेजुएला के लिए अमेरिकी सरकार के समर्थन को दोहराया है।

रोड्रिगेज ने टेलीग्राम पर लिखा कि ट्रम्प और रुबियो ने बचाव कार्यों में मदद जारी रखने का भरोसा दिया। इसके तहत बचावकर्मियों की तैनाती, विशेष उपकरण, अस्थायी आश्रय स्थलों के लिए सहायता और प्रभावित परिवारों के लिए मानवीय मदद भेजने की बात कही गई है।

वेनेजुएला के लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन 'अमिस्ताद'... भारत ने शुक्रवार को वेनेजुएला की मदद के लिए 'ऑपरेशन अमिस्ताद' शुरू किया है। 'अमिस्ताद' एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब 'दोस्ती' होता है। वेनेजुएला की आधिकारिक भाषा स्पेनिश ही है। इस ऑपरेशन का मकसद भूकंप प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द मदद पहुंचाना और घायलों का इलाज कराना है। भारतीय वायुसेना के दो ष्ट-17 ग्लोबमास्टर विमानों के जरिए करीब 35 टन राहत सामग्री भेजी गई है।

मप्र.-झारखंड में आंधी-बिजली से 16 की मौत

उत्तराखंड में घरों-स्कूलों में मलबा घुसा, गाड़ियां दबीं

» यूपी-राजस्थान-हरियाणा में तापमान 42 डिग्री पार

भोपाल/जयपुर/लखनऊ/पटना,एजेंसी। देश के 6 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में प्री-मानसून बारिश जारी है। हालांकि, छह राज्यों में तेज गर्मी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में पारा 42डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया।

मध्य प्रदेश के बालाघाट में शुक्रवार को बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग झुलस गए। देवास में आंधी-बारिश से मकान की बालकनी का हिस्सा गिर गया, हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं झारखंड में भी बिजली गिरने से 10 और छत्तीसगढ़ में दो लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के चमोली में देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद बादल फटने जैसी घटना हुई, जिससे स्कूल, 8 बड़ी गाड़ियां, एंबुलेंस और मकानों में मलबा घुस गया है।

मानसून ने देश के 22 राज्यों को कवर कर लिया है। 5 जुलाई तक बाकी राज्यों को कवर कर सकता है। यूपी में मानसून 8 दिन लेट है। यह आमतौर पर 20 जून तक आ जाता है लेकिन इस बार 15 दिनों से बिहार बॉर्डर पर रुका है। यह अगले 2 दिन में बिहार बॉर्डर से प्रदेश में एंट्री कर सकता है।

6 राज्यों में गर्मी का असर, पारा 40डिग्री पार... मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कई शहरों में बुधवार को पारा 40डिग्री से ज्यादा रहा। देश में सबसे ज्यादा पारा हरियाणा के रोहतक में 43.4डिग्री दर्ज किया गया। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में 43.2डिग्री, बांदा और आगरा में 43डिग्री, राजस्थान के श्रीगंगानगर में 42.1डिग्री, एमपी के ग्वालियर में 41.8डिग्री और गुजरात के अहमदाबाद में 41.7डिग्री रहा।

अध्ययन: भारत में बढ़ रही कुंवारों की संख्या, बेरोजगारी बड़ी वजह

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत में युवाओं के विवाह में देरी या अविवाहित रहने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। पहले माना जाता था कि यह समस्या केवल घटते लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या का परिणाम है, लेकिन एक नया अंतरराष्ट्रीय अध्ययन इस संकट के पीछे के अधिक जटिल और गहरे कारणों को उजागर करता है।

शोध के अनुसार, नौकरी की कमी और आर्थिक अस्थिरता आज युवाओं के विवाह में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। पॉपुलेशन स्टडीज में प्रकाशित इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विवाह का दायरा अब पूरी तरह बदल चुका है। वधू पक्ष अब ऐसे वर की तलाश में है जिसके पास स्थायी नौकरी और वित्तीय सुरक्षा हो। नतीजतन, बड़ी संख्या में युवा पुरुष विवाह के दायरे से बाहर होते जा रहे हैं।

जीवनसाथी के लिए सबसे लंबा इंतजार बेरोजगारों का: शोधकर्ताओं ने भारतीय युवाओं को तीन श्रेणियों में बांटा है। प्रथम वर्ग में वे युवा हैं जो कम शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं। दूसरे वर्ग में शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवा शामिल हैं, और तीसरे वर्ग में वे युवा हैं जो शिक्षित हैं और जिनके पास स्थायी रोजगार है। स्पष्ट है कि विवाह के दायरे में तीसरे वर्ग की ही मांग सबसे अधिक है, जबकि पहले दो वर्गों के युवाओं को जीवनसाथी की तलाश में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि बेरोजगारी के कारण बड़ी संख्या में युवा लगातार उच्च शिक्षा और डिग्रियां हासिल करने में जुटे हैं, ताकि वे किसी तरह स्थायी नौकरी पा सकें। इस प्रयास में वे विवाह को तब तक टालते रहते हैं, जब तक वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हो जाएं। इससे विवाह की औसत आयु लगातार बढ़ रही है।

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हो रही पैदा...

शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती है। बड़ी संख्या में बेरोजगार, अविवाहित और निराश युवाओं में हताशा और असंतोष का बढ़ना समाज के लिए चिंता का विषय है। यदि इस आर्थिक अनिश्चितता को जल्द दूर नहीं किया गया, तो आने वाले समय में विवाह संकट और गहरा सकता है, जिससे देश के समृद्ध सामाजिक ताना-बाना के प्रभावित होने का खतरा है।

मुरैना में पति ने पत्नी और दो मासूम बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा

» पुलिस बोली-पत्नी के डांस वीडियो से नाराज था

फिर ट्रेन से कटकर दी जान

मुरैना,एजेंसी। मुरैना जिले के किशनपुर गांव में शुक्रवार रात 35 वर्षीय बलराम सिंह कुशवाहा ने पहले अपनी पत्नी और दो मासूम बेटों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद गांव से कुछ दूरी पर स्थित शिकारपुर रेलवे फाटक पहुंचा और ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली।

सुबह खुला घटना का राज: बसैया थाना प्रभारी विवेक तोमर ने बताया कि वारदात घर के आंगन में हुई। घर चारों ओर से ऊंची बाउंड्री से घिरा हुआ है। शनिवार सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का मुख्य गेट बाहर से बंद है। शक होने पर उन्होंने बाउंड्री के ऊपर से अंदर झांक कर देखा तो महिला और दोनों बच्चों के शव पड़े मिले। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

तीनों की मौके पर ही मौत हो गई: पुलिस के मुताबिक, बलराम सिंह ने देर रात सो रही अपनी 32 वर्षीय पत्नी रविता कुशवाहा पर कुल्हाड़ी से हमला किया। इसके बाद उसने अपने दोनों बेटों, 8 वर्षीय आरव और 5 वर्षीय देबू पर भी ताबड़तोड़ वार किए। हमले में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही माता बसैया थाना पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी है।

पत्नी के डांस वीडियो को लेकर नाराज था... पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि बलराम बेंगलुरू में मार्बल घिसाई का काम करता था। एक माह पहले ही गांव लौटा था। उसकी पत्नी रविता ने एक माह पहले गांव की भागवत कथा में डांस किया था, जिसका वीडियो गांव के कुछ लड़कों ने बनाकर बलराम को वॉट्सएप कर दिया था। इससे बलराम नाराज था। दोनों के बीच एक माह से विवाद चल रहा था। कुछ दिनों के लिए रविता मायके भी रहने चली गई थी। तीन दिन पहले ही लौटी थी। बताया जा रहा है कि बलराम रविता के बाजार जाने पर भी नाखुश रहता था।

अयोध्या राममंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच तिरुपति का बड़ा फैसला

आईसीएआई करेगा ऑडिट; यह सिस्टम बदल देगा सबकुछ

नई दिल्ली, एजेंसी। अयोध्या में श्रीरामलला मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) संचालित देश में सबसे अधिक चढ़ावा प्राप्त करने वाले मंदिरों में शामिल तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आ रहे चढ़ावे के पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह प्रबंधन के लिए बड़ा कदम उठाया है। टीटीडी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को चढ़ावा प्राप्त होने से लेकर उसकी गिनती, सुरक्षित रखरखाव, बैंक में जमा, हिसाब-किताब, लेखा परीक्षण और निगरानी के लिए नया अचूक प्रबंधन माडल तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। यह पहल ऐसे समय हुई है जब श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला चर्चा में है। तिरुमला मंदिर में भी चढ़ावा चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं।

लेखा-जोखा की पूरी प्रक्रिया का आकलन: आईसीएआई के अध्यक्ष सीए प्रसन्ना कुमार डी. ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आईसीएआई विशेषज्ञों की टीम पहले 100 दिनों तक चढ़ावे को लेकर मंदिर की मौजूदा व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करेगी। इस दौरान चढ़ावा प्राप्त होने से लेकर उसकी गिनती, सुरक्षित रखरखाव, बैंक में जमा और लेखा-जोखा तक पूरी प्रक्रिया का आकलन किया जाएगा। फिर ऐसा चढ़ावा प्रबंधन मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसे बड़े मंदिरों में उनकी आवश्यकता के अनुरूप लागू किया जा सके। कहाकि तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को वर्ष 2024 में 1,365 करोड़ का चढ़ावा प्राप्त हुआ था। प्रतिदिन यहां करोड़ों नकद के साथ सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी चढ़ावे में आती हैं। इतनी बड़ी मात्रा में आने वाले चढ़ावे का पारदर्शी, सुरक्षित और सटीक प्रबंधन अपने आप में बड़ी चुनौती है।

चढ़ावे की हो चुकी है चोरी: वर्ष 2023 में तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पराकामनी (चढ़ावे की गिनती) के दौरान एक कर्मचारी 900 अमेरिकी डालर चोरी करते पकड़ा गया था। इससे पहले वर्ष 2022 में भी चढ़ावे की गिनती के दौरान 20 हजार रुपये की चोरी का मामला सामने आया था। इन घटनाओं ने मंदिर प्रशासन के सामने चढ़ावा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया था। जिस पर अब यह कदम उठाया गया है।

अयोध्या के लिए नहीं कोई योजना: यह पूछने पर कि क्या आईसीएआई की अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के लिए भी ऐसा कोई माडल तैयार कर रहा है, सीए प्रसन्ना कुमार डी. ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अब तक कोई संपर्क नहीं किया है। भविष्य में ऐसा कोई आधिकारिक अनुरोध मिलता है तो आईसीएआई को वहां भी ऐसी व्यवस्था तैयार करने में गर्व होगा।

अध्ययन के मुख्य बिंदू

- चढ़ावा प्राप्त होने से लेकर बैंक में जमा होने तक हर चरण के लिए तय और पारदर्शी कार्यप्रणाली।
- नकद, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की अलग-अलग गिनती, वर्गीकरण और अभिलेख।
- प्रत्येक चरण में आवश्यकतानुसार दोहरी या बहुस्तरीय सत्यापन, ताकि पूरी प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे।
- चढ़ावे का डिजिटल लेखा-जोखा और हर चरण का सुरक्षित रेकार्ड।
- सीसीटीवी निगरानी और पूरी प्रक्रिया का डिजिटल रेकार्ड, डिजीटल गणना।
- गिनती से लेकर बैंक में जमा होने तक प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था।
- नियमित मिलान, आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षण।
- जोखिम प्रबंधन तथा किसी भी अनियमितता की समय रहते पहचान और रोकथाम की व्यवस्था।

बल्लभगढ़ में एसडीएम के आदेश हवा में 10 मतदान केंद्रों में से 9 के बीएलओ नदारद, जनता परेशान

फरीदाबाद (सुभाष डागर), एजेंसी। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 191 से लेकर 201 तक 10 मतदान केंद्रो पर सिर्फ 198 मतदान केंद्र के बीएलओ बैठकर मतदाताओं के फार्म जमा कर रहे हैं। अन्य नौ बूथ के बीएलओ कहां पर हैं यह किसी को पता नहीं है। बीएलओ सुपरवाइजर सुमित कुमार का कहना है कि अभी थोड़ी देर में ही अन्य बीएलओ आ जाएंगे। जबकि विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी एसडीएम मयंक भारद्वाज ने शुक्रवार को मीटिंग में सभी बीएलओ को अपने-अपने बूथ पर नौ बजे से शाम के छह बजे तक बैठने के लिए कहा था। निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी के नियमों का बीएलओ कितनी गंभीरता से पालन कर रहे हैं इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। केंद्र पर अपना फार्म जमा करने आए लोगों का कहना है कि वह कामकाज छोड़कर सुबह नौ बजे फार्म जमा करने के लिए यहां पर आ चुके हैं।

यीड़ा की 1000 करोड़ की 'हेरिटेज सिटी' परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, हरी झंडी मिलते ही लिया जाएगा किसानों की जमीन

ग्रेटर नोएडा, एजेंसी। मथुरा जिले में यीडा की हेरिटेज सिटी परियोजना को शासन की पीपीपी निविदा मूल्यांकन समिति से जल्द स्वीकृति मिल सकती है। यीडा बोर्ड निविदा प्रपत्र व शर्तों को पहले ही स्वीकृति दे चुका है। एक हजार करोड़ से अधिक की परियोजना होने के कारण इसे शासन की सचिव समिति व कैबिनेट से मंजूरी भी अनिवार्य है। फेज दो मास्टर प्लान में शामिल मथुरा जिले में यमुना प्राधिकरण की हेरिटेज सिटी परियोजना प्रस्तावित है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की 15.3 किमी लंबी सड़क के किनारे हेरिटेज सिटी को करीब 750 एकड़ में विकसित किया जाएगा। यह सड़क एनएच 44 को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बनाई जाएगी। हेरिटेज सिटी परियोजना में ध्यान केंद्र, कथा वाचनालय से लेकर होटल, हाट व पर्यटन के लिए अन्य सुविधाएं विकसित होंगी। परियोजना की निविदा को यीडा बोर्ड की पिछली बैठक में स्वीकृति दी गई थी। अब इसे औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पीपीपी निविदा मूल्यांकन समिति के सम्मुख स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। यीडा एसीईओ शैलेंद्र कुमार भाटिया ने बताया कि शासन को पत्र भेजकर समिति की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है। मथुरा जिला प्रशासन परियोजना के लिए जमीन की मुआवजा दर निर्धारित करने की प्रक्रिया में जुटा है।

औद्योगिक गलियारे का मास्टर प्लान तैयार करने को चयनित होगी कंपनी: एविएशन हब और फेज दो के बीच करीब आठ हजार हे. क्षेत्र के यीडा औद्योगिक गलियारे को तौर पर विकसित करेगा। प्राधिकरण इसका मास्टर प्लान तैयार करने जा रहा है। इसे तैयार करने के लिए कंपनी चयन की प्रक्रिया एक सप्ताह में शुरू होने जाएगी। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के जरिये कंपनियों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। कंपनी मास्टर प्लान के तहत निर्धारित क्षेत्र में औद्योगिक, आवासीय, सर्विस सेक्टर के लिए अपने सुझाव देगी।

'कब्जा मिलने के बाद भी बिल्डर से मुआवजे की मांग कर सकते हैं घर खरीदार सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। फ्लैट का कब्जा लेने के बाद भी घर खरीदार सर्विस में कमी के लिए रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदार फ्लैट का कब्जा लेने के बाद भी कब्जा मिलने में हुई देरी के लिए मुआवजा पाने के लिए डेवलपर्स के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें कहा गया था कि फ्लैट का कब्जा लेने के बाद घर खरीदार कंज्यूमर नहीं रह जाता और देरी के लिए मुआवजा नहीं मांग सकता।

कंज्यूमर फोरम जाने से नहीं रोका जा सकता: अदालत ने यह भी कहा कि घर खरीदार और रियल एस्टेट कंपनी के बीच हुए एग्रीमेंट में मौजूद आर्बिट्रेशन क्लॉज (मध्यस्थता की शर्त) खरीदार को अपनी शिकायतें लेकर कंज्यूमर फोरम में जाने से नहीं रोक सकता। एनसीआर के द्वारका में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट का कब्जा मिलने के बाईस साल बाद जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने फ्लैट सौंपने में हुई देरी के लिए मुआवजा मांगने की खरीदार की याचिका को मंजूरी दे दी। बेंच ने कहा कि एनसीडीआरसी का तर्क सही नहीं ठहराया जा सकता।

पीठ ने क्या कहा: बेंच ने कहा, 'अपीलकर्ता की शिकायत सिर्फ कब्जा पाने के बारे में नहीं थी। उसकी शिकायत यह थी कि फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी हुई थी और वह इस देरी के लिए मुआवजा पाने का हकदार था। कब्जा मिलने में देरी के लिए मुआवजे का दावा असल में कब्जा मिलने से पहले की अवधि से जुड़ा होता है। बाद में कब्जा मिल जाने से देरी के लिए मुआवजे के दावे पर फैसला पाने का अलॉटी (आवंटी) का अधिकार अपने-आप खत्म नहीं हो जाता। ' बेंच ने घर खरीदार की ओर से जिला उपभोक्ता फोरम में 2005 में दायर शिकायत को फिर से शुरू किया।

नौ साल बाद पूरा होगा 'टावर ऑफ जस्टिस' का सपना, सीजेआई सूर्यकांत करेंगे शुभारंभ

बादशाहपुर (गुरुग्राम), एजेंसी। जिला अदालत परिसर में बन रहे बहुचर्चित टावर ऑफ जस्टिस का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद तैयार हुए इस नए न्यायिक परिसर का शुभारंभ 12 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) सुर्यकांत द्वारा किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा ने जिला अदालत में तैनात सभी न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी न्यायिक अधिकारी और स्टाफ सदस्य 11 और 12 जुलाई को अपने स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को इन तिथियों में स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में ही

पूर्व अनुमति के बाद अवकाश दिया जाएगा। 2014 में शुरू हुआ था निर्माण, नौ साल में बदली कई समय सीमाएं टावर आफ जस्टिस परियोजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसे गुरुग्राम में न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में देखा गया था। शुरुआत में निर्माण कार्य वर्ष 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तय समय पर काम पूरा नहीं हो सका। इसके बाद समय सीमा बढ़ाकर 2020, फिर 2024 और बाद में 2025 तक की गई। अब यह परियोजना वर्ष 2026 में जाकर पूरी होने जा रही है।

113 करोड़ की परियोजना पहुंची करीब 295 करोड़ तक: परियोजना में देरी का असर इसकी लागत पर भी पड़ा। शुरुआती अनुमान के अनुसार निर्माण पर करीब 113 करोड़ रुपये खर्च होने थे, लेकिन तकनीकी बदलाव, निर्माण में देरी और अन्य प्रशासनिक कारणों से इसकी लागत बढ़कर लगभग 295 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

एक छत के नीचे मिलेंगी न्यायिक सुविधाएं

टावर आफ जस्टिस का उद्देश्य जिला एवं सत्र न्यायालय की विभिन्न अदालतों, प्रशासनिक कार्यालयों और न्यायिक सुविधाओं को एक ही परिसर में लाना है। इससे न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी और आम लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।परियोजना में देरी के पीछे तकनीकी अड़चनें, डिजाइन में बदलाव, प्रशासनिक समन्वय की कमी और निर्माण की धीमी गति जैसे कारण बताए जाते रहे हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सक्रियता के बाद शेष कार्यों को तेजी से पूरा किया गया।

ब्राह्मण होने की वजह से पहली पंक्ति में बैठने से रोका गया', बीजेपी सांसद ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर लगाया आरोप

पुणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के पुणे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हुए मराठा उम्मीदवारों के सम्मान समारोह के दौरान बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर उन्हें अगली पंक्ति में बैठने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वह ब्राह्मण हैं। हालांकि, जिन विधायक अभिमन्यु पवार पर उन्होंने यह आरोप लगाया उन्होंने कहा कि यह एक गलतफहमी थी और इस बात से इनकार किया कि इस मामले में जाति कोई मुद्दा था।

कार्यक्रम में सीएम फडणवीस थे मौजूद: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम का आयोजन मराठा समुदाय के उन उम्मीदवारों के सम्मान के लिए किया गया था, जिन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी), महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (एमपीएससी) और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किए थे।

कुलकर्णी ने क्या आरोप लगाया: कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि पवार ने उन्हें पहली पंक्ति में बैठने से रोका और कहा कि यह कार्यक्रम मराठा समुदाय के लिए था। उन्होंने कहा कि इस आदेश के तुरंत बाद वह कार्यक्रम से चली गईं। उन्होंने कहा, 'चूंकि कोई अन्य सांसद मौजूद नहीं था इसलिए अधिकारियों का मानना था कि प्रोटोकॉल के अनुसार मैं पहली पंक्ति में बैठ सकती हूं। अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल के अध्यक्ष नरेंद्र पाटिल भी वहां बैठने के हकदार थे। ' कुलकर्णी ने दावा किया, 'हालांकि, अभिमन्यु पवार पहली पंक्ति में बैठना चाहते थे। जब अधिकारियों ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार मैं वहां बैठ सकती हूं तो पवार ने जाति का मुद्दा उठाया और कहा कि चूंकि कार्यक्रम मराठा समुदाय के लिए था, इसलिए मेरे पहली पंक्ति में बैठने से विवाद हो सकता है। '

आरोपों पर विधायक ने क्या कहा: इन आरोपों का जवाब देते हुए लातूर जिले के औसा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पवार ने जाति का मुद्दा होने से इनकार किया और कहा कि गलतफहमी हुई थी। उन्होंने कहा, 'मैंने बस इतना कहा था कि चूंकि नरेंद्र पाटिल महामंडल के अध्यक्ष हैं इसलिए वह पहली पंक्ति में बैठ सकते हैं, जबकि विधायक और सांसद दूसरी पंक्ति में बैठ सकते हैं। यहां जाति का कोई मुद्दा नहीं है। वहां कई लोग मौजूद थे और उन्होंने सुना कि मैंने क्या कहा।

जिनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन पीओजेके में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप

जिनेवा, एजेंसी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) ने शुक्रवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मुख्यालय के बाहर स्थित 'ब्रोकन चेयर' स्मारक पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 62वें सत्र के दौरान आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल पीओजेके में लोगों पर दमन कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से 7 जून को रावलाकोट में हुई गोलीबारी का जिक्र किया, जिसमें कई लोगों की मौत और कई अन्य घायल हुए थे।

संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग: यूकेपीएनपी के नेताओं जमील मकसूद और अमजद यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए ताकि वह अपनी सुरक्षा बलों को क्षेत्र से हटाए और रावलाकोट में जारी घेराबंदी खत्म करे।

स्वतंत्र जांच की मांग: प्रदर्शन के आयोजकों ने नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग और शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के आरोपों की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच कराने की मांग भी की। यूकेपीएनपी की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष जमील मकसूद ने कहा कि पार्टी पीओजेके के लोगों पर कथित दमन और आतंक के खिलाफ आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान से सुरक्षा बल हटाने और रावलाकोट की घेराबंदी समाप्त करने के लिए कहना चाहिए।

'दो लाख लोग धरने पर': यूकेपीएनपी के सदस्य अमजद यूसुफ ने दावा किया कि रावलाकोट में करीब दो लाख लोग अपने बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाली गैर-राजनीतिक संस्था जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है और उसके सदस्यों पर इनाम घोषित कर दिया है।

खाद्य और दवाओं की कमी का आरोप: अमजद यूसुफ ने कहा कि इलाके में हालात बेहद गंभीर हैं। उनके मुताबिक, पिछले 12 दिनों से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। भोजन और दवाओं की कमी है, स्कूल और अस्पताल बंद हैं तथा इंटरनेट सेवाएं भी काफी हद तक बाधित हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घायल लोगों का इलाज कराने के बजाय उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और स्थानीय नेतृत्व उत्पीड़न के डर से क्षेत्र छोड़ने को मजबूर हो गया है।

पाकिस्तान के दावों पर सवाल: यूकेपीएनपी और जेएएसी के प्रतिनिधियों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार भले ही हालात सामान्य होने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी स्थिति इससे अलग है।

जंग के बीच रूस-यूक्रेन ने की कैदियों की अदला-बदली, 76वीं बार युद्धबंदियों की रिहाई

मॉस्को, एजेंसी। रूस और यूक्रेन ने शुक्रवार को एक बार फिर युद्धबंदियों की अदला-बदली की। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार, इस बार दोनों तरफ से 160-160 कैदियों को छोड़ा गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके से 160 रूसी सैनिकों को वापस लाया गया, जबकि इसके बदले 160 यूक्रेनी युद्धबंदियों को छोड़ा गया। मंत्रालय के मुताबिक, वापस आए रूसी सैनिकों को पहले बेलारूस में चिकित्सा और मानसिक सहायता दी जा रही है। इसके बाद उन्हें आगे इलाज और देखभाल के लिए रूस भेजा जाएगा।

यूएई ने निभाई मध्यस्थ की भूमिका: समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, इस अदला-बदली में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मानवीय मदद और मध्यस्थता की भूमिका निभाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि रिहा किए गए यूक्रेनी सैनिक 2022 से कैद में थे। जेलेंस्की ने कहा कि इनमें यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जवान, स्टेट स्पेशल ट्रांसपोर्ट सर्विस, नेशनल गार्ड और स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस के सदस्य शामिल हैं। शुक्रवार की यह अदला-बदली 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच 76वीं कैदी अदला-बदली थी।

रूसी मानवाधिकार आयुक्त की यूक्रेनी समकक्ष से मुलाकात: रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, रूस की मानवाधिकार आयुक्त याना लांत्रोवा ने मानवीय बातचीत जारी रखने के लिए बेलारूस-यूक्रेन सीमा पर अपने यूक्रेनी समकक्ष दिमित्री लुबिनेट्स से मुलाकात की।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा: रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा, यूएई ने मानवीय मध्यस्थता के जरिए रूसी सैनिकों को वापस लाने में मदद की।

ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कबूला जुर्म गोपनीय दस्तावेज मामले में दोषी करार

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके जॉन बोल्टन ने गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को अवैध रूप से अपने पास रखने के मामले में अदालत में दोष स्वीकार कर लिया है। बोल्टन ने शुक्रवार को अमेरिकी अदालत में अपना जुर्म कबूल किया। इस मामले में उनके और अमेरिकी न्याय विभाग के बीच समझौता भी हुआ है, जिससे उन्हें जेल की सजा से राहत मिल सकती है। हालांकि अंतिम फैसला अदालत ही सुनाएगी। 77 वर्षीय जॉन किरियाको नहीं, बल्कि जॉन बोल्टन ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे थे। उन्होंने मैरीलैंड के ग्रीनबेल्ट स्थित अमेरिकी जिला अदालत में राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी को अवैध रूप से अपने पास रखने के एक मामले में दोषी होने की बात स्वीकार की। इस अपराध के लिए अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। बोल्टन को 28 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए बोल्टन को भयानक व्यक्ति बताया और कहा कि उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए।

जॉन बोल्टन पर क्या आरोप लगे थे: अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, बोल्टन पर पिछले साल अक्टूबर में कुल 18 आरोप लगाए गए थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान तैयार की गई डायरी जैसी निजी नोट्स और अन्य गोपनीय जानकारियां अपने पास रखीं और उनमें से कुछ को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा भी किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक, बोल्टन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपने दैनिक कार्यों से जुड़ी 1,000 से अधिक पन्नों की जानकारी अपने परिवार को भेजी थी।

क्या समझौते से जेल की सजा टल सकती है: न्याय विभाग के साथ हुए समझौते के तहत बोल्टन ने 22.5 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने पर सहमति जताई है। उन्हें अपनी संघीय सेवा से मिलने वाली सेवानिवृत्ति राशि भी छोड़नी होगी। इसके अलावा उन्हें खुफिया अधिकारियों के साथ पूछताछ सत्र में शामिल होना होगा और 100 घंटे तक सामुदायिक सेवा भी करनी होगी। समझौते में जेल की सजा को अधिकतम पांच साल तक सीमित रखने की सिफारिश की गई है, लेकिन अदालत इस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

जांच के दौरान क्या सामने आया: अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, बोल्टन ने कुछ दस्तावेज अपनी पत्नी और बेटी के साथ साझा किए थे। एक दस्तावेज भेजने के बाद उन्होंने संदेश में लिखा था, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभियोजकों का कहना है कि हालांकि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि उनके परिवार ने यह जानकारी किसी और को दी। लेकिन सरकारी सेवा छोड़ने के बाद बोल्टन के निजी ईमेल खाते को ईरान से जुड़े एक हैकर ने निशाना बनाया था, जिससे गोपनीय जानकारी तक पहुंच बनने की आशंका जताई गई।

ट्रंप और बोल्टन के रिश्ते क्यों खराब हुए थे: जॉन बोल्टन ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में एक साल से अधिक समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम किया था। वर्ष 2019 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने द रूम व्हेयर इट हैपन्ड नामक पुस्तक लिखी, जिसमें ट्रंप के नेतृत्व की आलोचना की गई थी। ट्रंप प्रशासन ने इस पुस्तक के प्रकाशन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद से ट्रंप और बोल्टन के बीच सार्वजनिक तौर पर कई बार तीखी बयानबाजी भी हुई।

द्य

डीईओ के आदेश पर मचा विवाद

पत्रकारों के विद्यालय प्रवेश पर रोक के निर्देश वापस होंगे, पत्रकार शब्द हटाने की तैयारी

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले की नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कविता त्रिपाठी द्वारा जारी एक प्रशासनिक आदेश विवादों में घिर गया है 25 जून को जारी आदेश में सभी शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों और संस्था प्रमुखों को निर्देश दिए गए थे कि बिना सक्षम अनुमति के पत्रकारों एवं आम नागरिकों को विद्यालय परिसर में प्रवेश न दिया जाए आदेश के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पत्रकार संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। बढ़ते विवाद के बीच डीईओ ने सफाई देते हुए कहा कि आदेश में 'पत्रकार' शब्द उनके निर्देश पर नहीं बल्कि लिपिकीय त्रुटि के कारण शामिल हो गया था और इसे संशोधित किया जाएगा।

जारी आदेश में विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा शासकीय कार्यों में अनावश्यक व्यवधान रोकने का हवाला देते हुए अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर नियंत्रण की बात कही गई थी हालांकि आदेश में पत्रकारों का भी उल्लेख होने से इसे मीडिया की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा गया और विभिन्न स्तरों पर इसकी आलोचना शुरू हो गई। विवाद बढ़ने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भी पत्रकार को समाचार संकलन से रोकना नहीं था उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में कई महिला प्राचार्यों ने शिकायत की थी कि कुछ अनधिकृत लोग विद्यालय परिसर में प्रवेश कर वीडियो बनाते हैं और बाद में उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर परेशान करते हैं इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने केवल अनधिकृत प्रवेश रोकने के संबंध में आदेश तैयार करने के निर्देश दिए थे।

डीईओ के अनुसार आदेश का मसौदा तैयार करते समय संबंधित लिपिक ने 'पत्रकार' शब्द जोड़ दिया जबकि उनका ऐसा कोई आशय नहीं था। उन्होंने कहा कि आदेश में आवश्यक संशोधन कर पत्रकार शब्द हटा दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी न रहे उन्होंने यह भी कहा कि बतौर जिला शिक्षा अधिकारी यह उनकी पहली पदस्थापना है और उनका मुख्य उद्देश्य जिले की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा विद्यालयों में सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखना है।

इधर,इस आदेश का पत्रकार संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। श्रमजीवी पत्रकार संगठन के जिला अध्यक्ष सुग्रीव वर्मा ने कहा कि जिले के इतिहास में पहली बार किसी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्रकारों के विद्यालय प्रवेश को लेकर इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है उनका कहना है कि मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और पत्रकारों को खबर संकलन से रोकने जैसा कोई भी कदम पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना के विपरीत माना जाएगा पत्रकार संगठनों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों और विप दलों ने भी आदेश पर सवाल उठाते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है उनका कहना है कि प्रशासनिक संस्थानों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मीडिया की स्वतंत्र भूमिका आवश्यक है और ऐसे आदेश अनावश्यक विवाद को जन्म देते हैं। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश में संशोधन का भरोसा दिया है और स्पष्ट किया है कि पत्रकारों के समाचार संकलन पर किसी प्रकार की रोक लगाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। अब सभी की नजर संशोधित आदेश पर टिकी है जिससे यह विवाद समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक आदेशों की भाषा, पारदर्शिता और मीडिया की भूमिका को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है।

न्यू पुलिस लाइन की जर्जर इमारत से गिरा छत का प्लास्टर, खेल रहे बच्चे बाल-बाल बचे, बड़ी दुर्घटना टली

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सिविल लाइन स्थित न्यू पुलिस लाइन में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया बी ब्लॉक की एक जर्जर आवासीय इमारत से छत का प्लास्टर अचानक भरभराकर नीचे गिर गया जिस स्थान पर यह घटना हुई, उसके आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे लेकिन समय रहते हट जाने से एक बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना दोपहर के समय हुई जब इमारत के अंदर और आसपास गतिविधियां चल रही थीं अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा जिससे वहां रखी कुर्सियां और घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गए तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है इसके दो दिन पहले भी इसी भवन से छत का प्लास्टर गिर चुका है लगातार हो रही इन घटनाओं के बावजूद अब तक किसी तरह की मरम्मत या सुरक्षा उपाय नहीं किए जाने से पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार न्यू पुलिस लाइन की ये आवासीय इमारतें लगभग 16 वर्ष पुरानी हैं समय के साथ-साथ उचित रखरखाव और मरम्मत के अभाव में ये भवन काफी जर्जर हो चुके हैं कई स्थानों पर दीवारों में दरारें दिखाई दे रही हैं जबकि छतों से प्लास्टर उखड़ने की घटनाएं आम हो गई हैं इससे इन इमारतों में रहना खतरे से खाली नहीं रह गया है। रहवासियों का आरोप है कि भवनों की खराब स्थिति को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

कोटवार नियुक्ति पर विवाद: सरपंच के बेटे को नियुक्त करने का आरोप, पीड़ित ने चौथी बार कलेक्टर से की शिकायत

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत ग्राम गोड़ाही में कोटवार पद की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है गांव के निवासी रामदेव बंसल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर विकास मिश्रा को आवेदन सौंपते हुए गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है उन्होंने दावा किया है कि कोटवार पद पर नियमों को दरकिनार कर सरपंच के बेटे की नियुक्ति की गई है पीड़ित रामदेव बंसल का कहना है कि उनके पिता के निधन के बाद परंपरागत एवं प्रशासनिक नियमों के अनुसार उन्हें कोटवार पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था उनका आरोप है कि ग्राम पंचायत स्तर पर उनके पक्ष में प्रस्ताव भी पारित किया गया था लेकिन इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया और ग्राम सरपंच के पुत्र देवेश कुशवाहा को कोटवार पद पर नियुक्त कर दिया गया रामदेव बंसल ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में जनपद पंचायत के एक कर्मचारी की मिलीभगत रही है जिसके चलते उनके अधिकारों की अनदेखी की गई उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नियमों के विरुद्ध बताया और कहा कि यह स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली लोगों के दबाव में लिया गया निर्णय है पीड़ित ने बताया कि यह मामला केवल नियुक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें व्यक्तिगत रंजिश भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व में गांव में अवैध शराब बिक्री की शिकायत की थी जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की थी उनका कहना है कि इसी कारण उनसे नाराजगी रखी गई और उन्हें कोटवार पद से वंचित किया गया। रामदेव बंसल ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले में एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रशासन से शिकायत की है यह चौथी बार है जब वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और न्याय की गुहार लगाई है उनका कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई जिससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद कमजोर होती जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है कुछ ग्रामीणों का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई जिससे विवाद की स्थिति बनी है वहीं प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की जांच की मांग लगातार उठ रही है।

सीधी जिला अस्पताल को मिले दो एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, सीजेरियन प्रसव सेवाओं में सुधार की उम्मीद

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के जिला अस्पताल में लंबे समय से चली आ रही निश्चेतना विशेषज्ञ (एनेस्थीसिया) की कमी अब दूर हो गई है रीवा संभाग के क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, डॉ. जीएस परिहार द्वारा जारी आदेश के तहत सीधी जिला अस्पताल को दो नए एनेस्थीसिया विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराए गए हैं इस निर्णय से अस्पताल में प्रसव सेवाओं, विशेषकर सीजेरियन डिलीवरी में आने वाली बाधाओं के समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है जिला अस्पताल में अब तक केवल एक ही निश्चेतना विशेषज्ञ कार्यरत था जिसके कारण कई बार आपातकालीन परिस्थितियों में भी सीजेरियन प्रसव समय पर नहीं हो पाते थे स्थिति यह थी कि गंभीर मामलों में प्रसूताओं को अन्य जिलों या उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर करना पड़ता था जिससे समय पर इलाज न मिलने का जोखिम बना रहता था जानकारी के अनुसार सीधी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने जिला अस्पताल में अतिरिक्त निश्चेतना विशेषज्ञों की तैनाती के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा था इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए थे इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप यह नई व्यवस्था लागू की गई है जारी आदेश के अनुसार रीवा जिले के दो सिविल अस्पतालों–सिरमौर और त्योंथर–से निश्चेतना विशेषज्ञों को सीधी जिला अस्पताल में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है बताया गया है कि वर्तमान में इन दोनों अस्पतालों में सीजेरियन प्रसव सेवाएं क्रियाशील नहीं हैं जिसके चलते वहां कार्यरत विशेषज्ञों को जनहित में सीधी जिला अस्पताल में सेवाएं देने के लिए स्थानांतरित किया गया है नए आदेश के तहत सिविल अस्पताल सिरमौर में पदस्थ एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. अजीत सिंह प्रत्येक सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को सीधी जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगे।

कलेक्ट्रेट परिसर में गंदगी का अंबार: पान-गुटखे की पीक से लाल हुई दीवारें, स्वच्छता व्यवस्था पर उठे सवाल

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में स्वच्छता का संदेश देने वाले कलेक्ट्रेट परिसर की बदहाल स्थिति ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं कलेक्ट्रेट की सफेद दीवारें पान और गुटखे की पीक से लाल दिखाई दे रही हैं जबकि कई कार्यालयों के बाहर कूड़ा-करकट और गंदगी फैली हुई है तहसीलदार, एसडीएम, अपर कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के कार्यालयों के आसपास फैली अव्यवस्था ने स्वच्छता अभियान की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है शनिवार दोपहर करीब 12 बजे कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करने पर कई स्थानों पर पान-गुटखे की पीक, कूड़े के ढेर और गंदगी दिखाई दी सीढ़ियों, गलियारों और कार्यालयों के प्रवेश द्वारों के पास जगह-जगह थूक के निशान नजर आए इतना ही नहीं परिसर में पेयजल व्यवस्था के आसपास भी स्वच्छता के अभाव के कारण गंदगी फैली हुई थी जिससे वहां आने वाले कर्मचारियों और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ कर्मचारी कार्यालय परिसर के भीतर ही पान और गुटखे का सेवन करते हैं और बाहर जाकर थूकने के बजाय भवन के आसपास ही पीक फेंक देते हैं इससे न केवल कार्यालय की सुंदरता प्रभावित हो रही है बल्कि सरकारी भवन की गरिमा भी धूमिल हो रही है लगातार हो रही इस लापरवाही के बावजूद परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रभावी निगरानी या अनुशासनात्मक कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है उल्लेखनीय है कि कलेक्टर विकास मिश्रा ने पदभार ग्रहण करने के बाद जिले में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया था उन्होंने स्वयं विभिन्न नदियों, तालाबों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान में भाग लेकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया था ऐसे में कलेक्टर कार्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित प्रशासनिक भवनों में फैली गंदगी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा रही है लोगों का कहना है कि यदि जिले के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय की यह स्थिति है।

हर दुकान पर दो डस्टबिन रखना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लगेगा 5 हजार रुपये का जुर्माना

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। मऊगंज नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने नगर परिषद क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर गीले एवं सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन नहीं पाए जाने पर नाराजगी जताई इसके बाद उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए अब नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक व्यापारी और नागरिक के लिए दो अलग-अलग डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया गया है आदेश का उल्लंघन करने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने नगर परिषद मऊगंज के भ्रमण के दौरान शहर की साफ-सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का निरीक्षण किया निरीक्षण के समय कई दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कुछ मकानों के बाहर गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण की उचित व्यवस्था नहीं मिली इस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कचरे का स्त्रोत स्तर पर पृथक्करण सुनिश्चित कराया जाए ताकि स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाया जा सके। कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक और सामाजिक दायित्व है यदि कचरे को उसके उत्पन्न होने वाले स्थान पर ही अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाए तो उसके संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल हो सकती है उन्होंने कहा कि गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर शहर के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जाहिर सूचना

क्र0-08/25 दिनांक-27/06/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीरथी सोनी पिता सीताशरण सोनी, निवासी वार्ड नं0-15/2472, गुलाब नगर, रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) का निवासी हैं, तथा डिजिटल ई-रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP30IGR18282026100148974 दिनांक 06/02/2026 विक्रेता राजेश जायसवाल से क्रेता भागीरथी सोनी ने खसरा नं0-163/8/2 रकवा 640.17 वर्गफिट अर्थात 0.007 हे0 स्थित ग्राम रतहरी, पटवारी हल्का पटवारी रतहरा, तहसील हुजूर नगर, जिला रीवा (म0प्र0) क्रय की थी तथा इसी प्रकार ई-रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP3284920181442196 दिनांक 23/06/2018 विक्रेता प्रखर गुप्ता एवं प्रवीण गुप्ता से क्रेता राजेश जायसवाल ने क्रय की थी। उपरोक्त मूल ई-रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP3284920181442196 दिनांक 23/06/2018 राजेश जायसवाल ने भागीरथी सोनी को प्रदान की गई थी जो कि भागीरथी सोनी से उक्त मूल ई-रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP3284920181442196 दिनांक 23/06/2018 कहीं गुम हो गई है, जिसकी सूचना भागीरथी सोनी द्वारा थाना समान को दी गई है, तथा काफी खोजबीन के पश्चात नही मिल रही है। वर्तमान समय में भागीरथी सोनी द्वारा उक्त भूमि को बंधक कर कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, शाखा रीवा (म0प्र0) से वित्तीय सहायता प्राप्त किया जा रहा है। जिसमें उक्त मूल ई-रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP3284920181442196 दिनांक 23/06/2018 की आवश्यकता है। भागीरथी सोनी पिता सीताशरण सोनी, निवासी वार्ड नं0-15/2472, गुलाब नगर, रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा उक्त भूमि को कहीं विक्रय, बंधक, गहन आदि करने तथा ऋण के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति। संस्था को कोई भी आपति हो तो वह इस प्रकाशन के सात दिवस के अंदर मेरे कार्यालय अथवा कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, शाखा रीवा (म0प्र0) में प्रस्तुत करे। प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी तथा भावी ऋण प्रदान कर दिया जावेगा।

भवदीय
राजेन्द्र त्रिपाठी एडवोकेट,
रीवा (म0प्र0)

ग्राम पंचायत पटेहरा में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को दिलाई नशा छोड़ने की शपथ

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। जिले में नशा मुक्त भारत अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत पटेहरा में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया कलेक्टर संजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन रमाशिव बहुदेशीय विकास समिति द्वारा किया गया चौपाल के माध्यम से आयोजित इस अभियान में ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा स्वस्थ, सुरक्षित और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 'नशा मुक्त भारत, विकसित भारत की पहचान विषय पर विस्तृत चर्चा की गई वक्ताओं ने बताया कि नशे की लत केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है इसलिए नशे से दूरी बनाकर स्वस्थ जीवन अपनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है अभियान के अंतर्गत 17 जून से 26 जून तक मनाए गए नशा मुक्त भारत सप्ताह के अवसर पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उपस्थित लोगों ने हस्ताक्षर कर यह संदेश दिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार तथा समाज के अन्य लोगों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी ग्रामीणों को नशा न करने तथा दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की सामूहिक शपथ दिलाई गई इस दौरान लोगों ने संकल्प लिया कि वे अपने गांव को नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और समाज में जनजागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे रमाशिव बहुदेशीय विकास समिति के अध्यक्ष विक्रांत द्विवेदी ने अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य समाज में नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना है उन्होंने कहा कि विशेष रूप से युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए तो नशामुक्त और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग के सुरक्षा अधिकारी अजय पटेल ने भी उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि नशे की लत कई सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं को जन्म देती है इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराए इस अवसर पर उमेश रावत एवं बीनू यादव ने भी कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सक्रिय सहयोग देने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उन्हें नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई साथ ही युवाओं को खेल, शिक्षा, रोजगार और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया ताकि वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रह सकें कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित लोगों से अपील की गई कि वे नशा मुक्त भारत अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने में सहयोग करें वक्ताओं ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता से ही नशामुक्त, स्वस्थ और विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है ग्रामीणों ने भी अभियान को सफल बनाने और अपने क्षेत्र को नशामुक्त बनाने का संकल्प दोहराया।

निर्णायक युद्ध हो

संपादकीय

किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी होती है। युवा केवल वर्तमान का आधार नहीं बल्कि भविष्य की दिशा और दशा निर्धारित करने वाली ऊर्जा हैं, किंतु जब यही ऊर्जा नशे की गिरफ्त में आ जाए तो वह राष्ट्र की प्रगति का इंजन बनने के बजाय उसके पतन का कारण बन जाती है। आज भारत एक ऐसे ही गंभीर सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां लाखों युवा नशे के दलदल में फंसकर अपने सपनों, परिवारों और भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। यही कारण है कि हर वर्ष 26 जून को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि समाज को चेताने वाला एक वैश्विक संदेश है कि यदि नशे की इस महामारी पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो इसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतने पड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1987 में 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस के रूप में घोषित किया था और 1989 से इसका नियमित आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने विश्व समुदाय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि वैश्विक ड्रग समस्या नए-नए रूपों में सामने आ रही है तथा इसके लिए नवाचार आधारित समाधान आवश्यक हैं। भारत में तो नशे की समस्या अब केवल स्वास्थ्य या कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गई है बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन चुकी है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल सहित लगभग सभी राज्यों में नशे का फैलता जाल चिंता का विषय है।

कभी हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध पंजाब आज नशे की समस्या के कारण राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका है। गांवों से लेकर शहरों तक अनेक परिवार ऐसे हैं, जिनका कोई न कोई सदस्य नशे की गिरफ्त में है। नशे के कारण युवाओं में एचआईवी, हेपेटाइटिस, मानसिक अवसाद, आत्महत्या और अपराध जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। स्थिति की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि नशे की शुरुआत करने की औसत आयु लगातार कम होती जा रही है। जो आयु कभी 17-18 वर्ष मानी जाती थी, वह अब किशोरावस्था तक सिमट गई है। स्कूलों और कॉलेजों के बाहर सक्रिय ड्रग नेटवर्क बच्चों और किशोरों को आसान निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स ने ड्रग तस्करों को नए हथियार उपलब्ध करा दिए हैं। आज नशे का कारोबार गली-मोहल्लों से निकलकर डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुका है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि नशे का स्वरूप भी बदल रहा है। पारंपरिक मादक पदार्थों के साथ-साथ सिंथेटिक ड्रग्स, मेथामफेटामिन, एमडीएमए, पार्टी ड्रग्स और रासायनिक नशीले पदार्थों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इनकी कीमत अपेक्षाकृत कम होती है और इन्हें छिपाकर ले जाना भी आसान होता है। वैश्विक स्तर पर भी कोकीन, सिंथेटिक ड्रग्स और अवैध ओपिओइड्स का बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। बहरहाल, नशे के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ने की जरूरत है।

आखिर नागरिकता साबित करने के लिए कौन-सा दस्तावेज वैध?

सौरभ

भारत में नागरिकता को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय बहस तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बाद कि पासपोर्ट अपने-आप में नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं है, विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि नागरिकता का निर्धारण केवल किसी एक दस्तावेज़ से नहीं, बल्कि कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र परीक्षण के आधार पर होता है। यह विवाद केवल कानूनी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिकों के भरोसे से भी जुड़ा है। आम नागरिक का सबसे बड़ा सवाल यही है–यदि आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड और यहां तक कि पासपोर्ट भी अंतिम प्रमाण नहीं हैं, तो आखिर भारतीय नागरिकता सिद्ध कैसे होगी? लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति नागरिक का विश्वास होता है। यदि नागरिक को अपने ही अधिकारों के प्रमाण को लेकर असमंजस रहे, तो यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं कही जा सकती। इसलिए समय की मांग है कि नागरिकता प्रमाणन की प्रक्रिया स्पष्ट, सर्वसुलभ और विवाद-मुक्त बनाई जाए, ताकि किसी भी भारतीय को अपनी नागरिकता साबित करने के प्रश्न पर अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पहचान और नागरिकता एक जैसी नहीं हैं। आधार कार्ड आपकी पहचान और निवास का प्रमाण है। वोटर आईडी मतदान के अधिकार का प्रमाण है। पैन कार्ड आयकर संबंधी पहचान है। ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देता है। पासपोर्ट विदेश यात्रा और अंतरराष्ट्रीय पहचान का दस्तावेज़ है। लेकिन इनमें से कोई भी दस्तावेज़ अकेले नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता।

आखिर नागरिकता कैसे तय होती है? भारत में नागरिकता का आधार नागरिकता अधिनियम, 1955 है। इस कानून के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख आधार हैं–जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिककरण द्वारा, किसी क्षेत्र के भारत में विलय के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न उठता है तो संबंधित प्राधिकारी उपलब्ध दस्तावेज़ों, जन्म संबंधी अभिलेखों, माता-पिता की नागरिकता, सरकारी रिकॉर्ड तथा अन्य कानूनी साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करता है। कोई एक दस्तावेज़ हर परिस्थिति में निर्णायक नहीं होता।

हाल के वर्षों में जन्म प्रमाण पत्र को सबसे महत्वपूर्ण आधार दस्तावेज़ों में माना जाने लगा है, क्योंकि इससे जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों का रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। लेकिन जिन लोगों का जन्म दशकों पहले हुआ और जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए स्कूल प्रमाणपत्र, भूमि अभिलेख, पारिवारिक रिकॉर्ड, सरकारी सेवा अभिलेख तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ भी परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं।

विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद विपक्ष ने प्रश्न उठाया कि यदि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, तो आम नागरिक किस दस्तावेज़ पर भरोसा करे। दूसरी ओर सत्तापक्ष का तर्क है कि दुनिया के अनेक देशों में भी पासपोर्ट नागरिकता निर्धारण का एकमात्र कानूनी आधार नहीं होता और विवाद की स्थिति में मूल नागरिकता रिकॉर्ड ही निर्णायक होते हैं। यह बहस संसद से लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों तक फैल चुकी है। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में आज तक ऐसा कोई एकल राष्ट्रीय नागरिकता प्रमाण-पत्र नहीं है जिसे हर स्थिति में अंतिम माना जाए। परिणामस्वरूप लोग आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज़ों को ही नागरिकता का प्रमाण समझ लेते हैं, जबकि कानून की दृष्टि से इनकी भूमिका अलग-अलग है। लोकतंत्र में केवल कानून होना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसका स्पष्ट और सरल संप्रेषण भी आवश्यक है। यदि नागरिकों में यह भ्रम बना रहे कि कौन-सा दस्तावेज़ वैध है और कौन-सा नहीं, तो इससे अनावश्यक भय और अफवाहें फैल सकती हैं।

सरकार को चाहिए कि नागरिकता प्रमाणन संबंधी एक स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करे, जिसमें बताया जाए कि विभिन्न

बदलते मौसम का बढ़ता जोखिम

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत में मानसून केवल एक ऋतु नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, जल-संसाधनों और जनजीवन की धुरी है। सदियों से मानसून को जीवनदायी माना जाता रहा है क्योंकि इसकी वर्षा खेतों को हरियाली देती है, नदियों और जलाशयों को भरती है तथा भीषण गर्मी से राहत प्रदान करती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मानसून का स्वरूप तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। अब यह केवल राहत लेकर नहीं आता, बल्कि अपने साथ अनेक प्रकार के जोखिम भी लेकर आता है। कहीं अचानक बादल फटने की घटनाएँ होती हैं, कहीं तेज़ हवाओं और गरज-चमक वाले तूफ़ानों से जनजीवन प्रभावित होता है, तो कहीं आकाशीय बिजली लोगों की जान ले लेती है। बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के दौर में मानसून से जुड़े खतरे पहले की तुलना में अधिक गंभीर और व्यापक हो गए हैं। यही कारण है कि मौसम संबंधी जोखिम आज केवल वैज्ञानिक अध्ययन का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानवीय चिंता का प्रश्न भी बन चुके हैं।

वर्तमान समय में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मौसम की पारंपरिक प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है। पहले जहाँ वर्षा अपेक्षाकृत नियमित और संतुलित होती थी, वहीं अब लंबे समय तक सूखा रहने के बाद अचानक अत्यधिक वर्षा होने लगी है। इसी प्रकार गरज-चमक वाले तूफानों और आकाशीय बिजली की घटनाओं में भी वृद्धि देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान ने वायुमंडल की संरचना और व्यवहार को प्रभावित किया है। वातावरण में अधिक ऊर्जा और अधिक नमी उपलब्ध होने के कारण मौसमीय घटनाएँ अधिक तीव्र और अनिश्चित हो रही हैं। इसका सीधा असर मानव जीवन, कृषि, बुनियादी ढाँचे और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है।

आकाशीय बिजली उन प्राकृतिक घटनाओं में से एक है जो हर वर्ष हजारों लोगों को प्रभावित करती है। भारत में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या कई अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में अधिक रहती है। विशेष चिंता का विषय यह है कि अधिकांश पीड़ित ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग खुले वातावरण में काम करते हैं। किसान, खेतिहर मजदूर, पशुपालक और निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिक मौसम के इन खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। जब अचानक बादल घिरते हैं और गरज-चमक शुरू होती है, तब कई लोग खतरे की गंभीरता को नहीं समझ पाते और खुले स्थानों पर ही बने रहते हैं। परिणामस्वरूप आकाशीय बिजली की चपेट में आकर अनेक लोगों की जान चली जाती है।

वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो आकाशीय बिजली का निर्माण वायुमंडल में होने वाली जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है। जब धरातल अत्यधिक गर्म हो जाता है और उसके ऊपर की परतों में अपेक्षाकृत ठंडी हवा मौजूद रहती है, तब गर्म और नम हवा तेजी से ऊपर उठने लगती है। यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। ऊपर उठती हुई हवा ठंडी होकर संघनित होती है और बादलों का निर्माण करती है। यदि वातावरण में पर्याप्त नमी और ऊर्जा मौजूद हो, तो ये बादल विशाल क्यूम्यलोनिम्बस बादलों का रूप ले लेते हैं। इन्हीं बादलों में पानी की बूंदों, बर्फ के कणों और ओलों

के बीच होने वाली टक्करों से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। जब आवेशों का असंतुलन अत्यधिक बढ़ जाता है, तब बिजली चमकती है और धरती तथा बादलों के बीच विद्युत निर्वहन होता है।

मानसून के दौरान समुद्रों से आने वाली नम हवाएँ भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पहुँचती हैं। ये हवाएँ बड़ी मात्रा में जलवाष्प लेकर आती हैं, जो बादलों के निर्माण और वर्षा के लिए आवश्यक होती है। लेकिन यही नमी जब अत्यधिक गर्म वातावरण से मिलती है, तो शक्तिशाली तूफानों का निर्माण भी कर सकती है। नमी और तापमान का यह संयोजन मौसमीय अस्थिरता को बढ़ाता है। यही कारण है कि मानसून के महीनों में गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएँ अधिक होती हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ेगा, वैसे-वैसे वायुमंडल अधिक नमी धारण करेगा और इस प्रकार की घटनाओं की संभावना भी बढ़ती जाएगी।

जलवायु परिवर्तन इस पूरे परिदृश्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। औद्योगीकरण, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई और अनियंत्रित शहरीकरण ने वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ा दी है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान में यह वृद्धि केवल गर्मी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे मौसम तंत्र को प्रभावित कर रही है। गर्म वातावरण अधिक नमी धारण करता है, जिससे तीव्र वर्षा और गरज-चमक वाले तूफानों की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि आज मौसम पहले की तुलना में अधिक अनिश्चित और चरम दिखाई देता है।

शहरीकरण भी मौसमीय जोखिमों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बड़े शहरों में कंक्रीट, डामर और भवनों की अधिकता के कारण हीट आइलैंड प्रभाव उत्पन्न होता है। इससे शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो जाता है। गर्म सतहें हवा को तेजी से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर बादलों और तूफानों के निर्माण की संभावना बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण भारी वर्षा होने पर जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याएँ भी गंभीर रूप धारण कर लेती हैं।

भारत की भौगोलिक विविधता भी मौसमीय घटनाओं को प्रभावित करती है। हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतों के कारण हवा तेजी से ऊपर उठती है, जिससे बादलों का निर्माण अधिक होता है। पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक नमी और पर्वतीय भूभाग मिलकर तीव्र वर्षा की परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। मध्य भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी और नमी का संयोजन गरज-चमक वाले तूफानों को जन्म देता है। वहीं तटीय क्षेत्रों में समुद्री हवाओं और भूमि की गर्मी के बीच अंतःक्रिया मौसमीय गतिविधियों को प्रभावित करती है। इस प्रकार भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपने-अपने भौगोलिक और जलवायु संबंधी कारकों के कारण अलग-अलग प्रकार के जोखिमों का सामना करता है।

मौसमीय जोखिमों का सबसे बड़ा प्रभाव समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर सुरक्षित आश्रयों और समय पर सूचना से वंचित रहते हैं। कई बार बिजली गिरने या तेज़ तूफान आने की चेतावनी जारी होने के बावजूद जानकारी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती। इसके अतिरिक्त, आर्थिक सीमाएँ भी लोगों को जोखिम उठाने के लिए मजबूर करती हैं। किसान और मजदूर अक्सर मौसम खराब होने के बावजूद काम जारी रखते हैं क्योंकि उनकी आजीविका उसी पर निर्भर होती है। ऐसी परिस्थितियों में प्राकृतिक जोखिम सामाजिक और आर्थिक जोखिमों में बदल जाते हैं।

मौसम संबंधी आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए केवल तकनीकी समाधान पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए जन-जागरूकता और मौसम-साक्षरता को बढ़ाना भी आवश्यक है। लोगों को यह समझाना होगा कि गरज सुनाई देने पर खुले स्थानों से दूर जाना क्यों आवश्यक है, ऊँचे पेड़ों के नीचे खड़े होना कितना खतरनाक हो सकता है और बिजली चमकने के दौरान किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। स्कूलों, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और मीडिया को इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यदि समाज मौसमीय जोखिमों को समझने लगे, तो अनेक जानें बचाई जा सकती हैं।

वर्तमान समय में मौसम विज्ञान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उपग्रह, डॉप्लर रडार, स्वचालित मौसम केंद्र और उन्नत कंप्यूटर मॉडल मौसम के पूर्वानुमान को अधिक सटीक बना रहे हैं। अब कई मामलों में गरज-चमक वाले तूफानों और बिजली गिरने की संभावना का पूर्वानुमान पहले से लगाया जा सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग और अन्य संस्थाएँ नियमित रूप से चेतावनियाँ जारी करती हैं। लेकिन चुनौती यह है कि इन चेतावनियों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुँचाया जाए और उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाए। केवल सूचना देना पर्याप्त नहीं है; यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि लोग उस सूचना को समझें और उसके अनुसार व्यवहार करें।

सरकारों को मौसमीय जोखिम प्रबंधन को विकास योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। बिजली गिरने की घटनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहाँ विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित सामुदायिक आश्रय बनाए जा सकते हैं। कृषि कार्यों के लिए मौसम आधारित सलाह प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है। स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मोबाइल तकनीक और डिजिटल संचार माध्यमों का उपयोग करके समय पर चेतावनी संदेश भेजे जा सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए दीर्घकालिक प्रयास भी आवश्यक हैं। वनों का संरक्षण, हरित ऊर्जा का विस्तार, कार्बन उत्सर्जन में कमी और टिकाऊ विकास की नीतियाँ भविष्य के जोखिमों को कम करने में मदद कर सकती हैं। यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया, तो मौसमीय घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ सकती हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन से निपटना केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि मानव सुरक्षा और सतत विकास की भी आवश्यकता है।

बदलते मौसम के इस दौर में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्राकृतिक घटनाएँ अब पहले जैसी नहीं रहीं। मानसून की वर्षा, गरज-चमक, तूफान और आकाशीय बिजली जैसी घटनाएँ अधिक जटिल और जोखिमपूर्ण होती जा रही हैं। इनसे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय वैज्ञानिक समझ, समय पर चेतावनी, जन-जागरूकता और सामुदायिक तैयारी है। यदि हम मौसम को केवल भाग्य या प्राकृतिक नियति मानकर छोड़ देंगे, तो जोखिम बढ़ते रहेंगे। लेकिन यदि हम विज्ञान, नीति और सामाजिक सहभागिता को साथ लेकर चलें, तो इन खतरों के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।मानसून भारत की जीवनरेखा है और आगे भी रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसके बदलते स्वरूप को समझें और उसके अनुरूप अपनी नीतियों, व्यवस्थाओं और व्यवहार में परिवर्तन करें। मौसमीय जोखिमों के प्रति सजग समाज ही भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकता है। बदलते मौसम के इस युग में तैयारी ही

स्नेही, संवेदनशील कवि थे ठाकुर बलदेव सिंह

हिमाचल एक शांत, परंतु संवेदनशील प्रदेश रहा है। कोई ज्यादा उछल-कूद नहीं, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं। बस लेखक हैं कि लिखने में ही आनंदोपलब्धि महसूस करते हैं। और बाहर की दुनिया तो यशपाल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी मात्र को ही हिमाचल की लेखकीय पहचान मानते हैं। मानें भी क्यों न। इन्हीं के नाम पर तो साहित्येतिहास में हिमाचल का नाम आता है। बात सही भी है। छोटा प्रदेश है, और यहां के लेखक टरटराते भी कम हैं और बिना टरटराए आवाज या एहसास दूर तक नहीं पहुंच पाता।

डा. सुशील कुमार फुल्ल

गत दो दशकों में हिमाचल के कतिपय लेखकों ने अपने प्रचार-प्रसार के प्रति रुचि दिखाई है और उनके प्रयत्नों से उनका नाम भी चर्चा में आने लगा है, परंतु जिस महानुभाव का स्मरण यहां मैं करना चाहता हूं, वह पुरानी पीढ़ी के सृजनकर्मी थे, जो किसी भी प्रकार के प्रचार को सही नहीं मानते थे। वह तो केवल साहित्यिक उपासना में लगे रहने में ही अपनी संतुष्टि ढूंढते थे। जी हां, ऐसे ही स्नेही, शांत जीव थे ठाकुर बलदेव सिंह, जिनका जन्म 3 जून, 1929 को कक्ड़ैं, सुलाह, तहसील पालमपुर में हुआ। पिता वैद थे और अपने क्षेत्र में विख्यात थे। अपने आप को एक शिक्षाविद के रूप में स्थापित किया

लेखन की दृष्टि से हिमाचल एक शांत, परंतु संवेदनशील प्रदेश रहा है। कोई ज्यादा उछल-कूद नहीं, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं। बस लेखक हैं कि लिखने में ही आनंदोपलब्धि महसूस करते हैं। और बाहर की दुनिया तो यशपाल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी मात्र को ही हिमाचल की लेखकीय पहचान मानते हैं। मानें भी क्यों न। इन्हीं के नाम पर तो साहित्येतिहास में हिमाचल का नाम आता है। बात सही भी है। छोटा प्रदेश है, और यहां के लेखक टरटराते भी कम हैं और बिना टरटराए आवाज या एहसास दूर तक नहीं पहुंच पाता। फिर भी गत दो दशकों में हिमाचल के कतिपय लेखकों ने अपने प्रचार-प्रसार के प्रति रुचि दिखाई है और उनके प्रयत्नों से उनका नाम भी चर्चा में आने लगा है, परंतु जिस महानुभाव का स्मरण यहां मैं करना चाहता हूं, वह पुरानी पीढ़ी के सृजनकर्मी थे, जो किसी भी प्रकार के प्रचार को सही नहीं मानते थे। वह तो केवल साहित्यिक उपासना में लगे रहने में ही अपनी संतुष्टि ढूंढते थे।

जी हां, ऐसे ही स्नेही, शांत जीव थे ठाकुर बलदेव सिंह, जिनका जन्म 3 जून, 1929 को कक्ड़ैं, सुलाह, तहसील पालमपुर में हुआ। पिता वैद थे और अपने क्षेत्र में विख्यात थे। मध्यमवर्गीय परिवार में जितना कोई पढ़ सकता था, बलदेव सिंह ने उससे ज्यादा ही पढ़ाई की और अपने आप को एक शिक्षाविद के रूप में स्थापित किया। एक-दो नहीं, बल्कि तीन-तीन विषयों में स्नातक स्तर की उपाधियां मैरिट के साथ अर्जित कीं और पंजाब के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान

जीएचजी बीबी हरप्रकाश कालेज ऑफ एजुकेशन, सिव्वां खुर्द में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हो गए। परंतु पहाड़ उन्हें वापस बुला रहे थे। पालमपुर के धनी एवं ख्यात परिवार ने कन्या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का निर्णय लिया और कन्हैया लाल बुटेल डीएवी कालेज फार गर्ल्ज की स्थापना हुई। इसके लिए उपयुक्त शिक्षाविद की जरूरत थी और श्री बृज बुटेल सिंधवां खुर्द से ठाकुर बलदेव सिंह को प्रिंसिपल बना कर ले आए। जो कन्या महाविद्यालय आज वटवृक्ष के रूप में दिखाई देता है और जिसके प्राचार्य आज युवा वैज्ञानिक डा. राजेंद्र सिंह राणा हैं, उसी संस्था के प्रथम प्रिंसिपल ठाकुर बलदेव सिंह वर्षों तक रहे और महाविद्यालय को शिखरों तक पहुंचाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। ठाकुर साहिब शिक्षाविद तो थे ही, परंतु साथ-साथ उनका कवि हृदय बहुत ही संवेदनशील था और यही कारण है कि उनके संस्थान में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का स्वर भी निरंतर गुंजायमान रहा। जब पालमपुर में कोई साहित्यिक संस्था नहीं थी, उसी समय सन सत्तर-पचहत्तर के आसपास रचना साहित्य एवं कला मंच पालमपुर का गठन हुआ और इसकी गतिविधियां केएलबी डीएवी कालेज में ही होती थीं। आतिथ्य ठाकुर बलदेव सिंह का ही रहता था। रचना पत्रिका का प्रकाशन भी उन्हीं दिनों में शुरू हुआ। डा. डीसी चंबयाल, डा. शमी शर्मा, अनेक नए लेखकों ने भी अपना नाम चमकाया।

आज भी डा. गुरमुख सिंह बेदी, मनोहर सागर पालमपुरी, डा. जियालाल, पीसीके प्रेम, सुदर्शन भाटिया, सरोज परमार, सुमन शेखर, डा. राजीव त्रिगर्ती, त्रिलोक मेहरा, सुशीला कटोच आदि अनेक लेखक मंच से जुड़े हैं। आज भी ठाकुर बलदेव सिंह का रोपा हुआ पौधा रचना मंच अपनी गतिविधियों से और पत्रिका के प्रकाशन के माध्यम से अपने आप को प्रासंगिक बनाए हुए है। डा. अरविंद ठाकुर, कल्याण जग्गी, डा. विजय पुरी, डा. सुदर्शना भटेरिया, सुरेशना अवस्थी, डा. आशु फुल्ल, डा. शिल्पी आदि अनेक लेखक आज भी रचना में सक्रिय हैं। साहित्य सृजन तो ठाकुर बलदेव सिंह पहले भी करते थे, परंतु मेरा मानना है कि रचना की नियमित गोष्ठियां होने के कारण उनका कद भी और गतिशील हो गया और उन्होंने कचोटती कसक, एक अन्य रचना तथा इस ओर उस ओर, तीन काव्य ग्रंथों का प्रणयन किया और पहाड़ी काव्य संग्रह के लिए उन्हें हिमाचल अकादमी का पुरस्कार भी मिला और उनकी पहाड़ी की कविताएं आंचलिक आस्वाद के कारण खूब सराही भी गई। कचोटती कसक में दैनंदिन जीवन की घटनाओं-अनुभवों को लेकर कई यथार्थवादी कविताएं लिखी गई हैं जो अपनी भाषा एवं भाव की सरसता के कारण प्रभावित करती हैं। पहाड़ी जीवन की झलक बेहद रोचक एवं आकर्षक ढंग से उकेरी गई है।

इस ओर उस ओर संग्रह में कवि वीत रागी हो गया है। जीवन के अंतिम दिनों में बीमारी के कारण परेशान थे ठाकुर साहिब। जैसे शेष अवस्थी अपने अंतिम दिनों में कैंसर की पीड़ा के कारण बहुत उदास और परेशान थे, उसी प्रकार जलोदर की बीमारी हो जाने के कारण बलदेव सिंह जी भी दुखी थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका इजहार नहीं किया। ठाकुर बलदेव सिंह ने अपना निजी प्रकाशन शुरू किया जिसका नाम था पांडव प्रकाशन, सुलाह। इसी प्रकाशन से उन्होंने अपनी तीन पुस्तकें छापी। बाद में निराश भी हुए कि कोई छापने को ही तैयार नहीं होता, रायल्टी की बात तो दूर की थी। उन्होंने एक कालजयी कहानी 'फिर मत कहना मैं वह बात बता दूंगी' शीर्षक से लिखी, एक एकांकी भी लिखा। बाकी शोधपत्र लिखे। कांगड़ी के वह विद्वान थे और विदेशों से छात्र उनके पास पढने आते थे। वह बहुत ही विनम्र थे और छात्र-छात्राओं की सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। साहित्य एवं शिक्षा जगत को उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका परलोक गमन 27 जून 2004 को हुआ। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन।

मुख्यमंत्री की संपत्ति पर सियासत तेज, विधायक प्रीतम लोधी ने कांग्रेस नेताओं की संपत्ति जांच की उठाई मांग

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संपत्ति को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि उनकी संपत्ति पहले से ही सार्वजनिक है और विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहा है साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की संपत्ति की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई प्रेस वार्ता के दौरान विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार से आते हैं उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री 'खानदानी रईस' हैं और उन्होंने चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में अपनी चल-अचल संपत्तियों का पूरा विवरण पहले ही सार्वजनिक कर दिया था। ऐसे में उनकी संपत्ति को लेकर सवाल उठाना तथ्यों से परे और केवल राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है विधायक ने कहा कि यदि किसी जनप्रतिनिधि की संपत्ति की जांच कराई जानी है तो यह प्रक्रिया निष्पक्ष और सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तथा पिछोर के पूर्व विधायक केपी सिंह का नाम लेते हुए कहा कि उनकी संपत्ति की भी जांच कराई जानी चाहिए उनका दावा था कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं प्रीतम लोधी ने आगे कहा कि विशेष रूप से केपी सिंह की संपत्ति की गहन जांच कराई जाए उन्होंने आरोप लगाया कि यदि ऐसा किया गया तो प्रदेश के नेताओं और कई उद्योगपतियों की तुलना में सबसे अधिक संपत्ति उनके नाम पर सामने आ सकती है। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज या साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा का भी उल्लेख किया उन्होंने कहा कि यदि नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग की जा रही है तो रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार जांच की प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि सभी प्रभावशाली लोगों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए भाजपा विधायक ने विपक्ष पर राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को उछालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उसका कोई ठोस आधार नहीं है उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने कानून के अनुसार अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक दस्तावेजों में पहले ही घोषित कर दिया है और इसमें किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं रखी गई फिलहाल मुख्यमंत्री की संपत्ति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है भाजपा और कांग्रेस दोनों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैंहालांकि इस मामले में संबंधित कांग्रेस नेताओं की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

दो यूट्यूबर्स पर ब्लैकमेलिंग की दूसरी एफआईआर

महिला से वीडियो हटाने के बदले पैसों की मांग का आरोप, पहले से जेल में बंद हैं आरोपी

मीडिया ऑडीटर, छत्तीसगढ़ (निप्र)। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े कथित इंस्टाग्राम चैट विवाद में गिरफ्तार दो यूट्यूबर्स सागर साहू और पुष्पराज सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं दोनों के खिलाफ अब ब्लैकमेलिंग और उगाही के आरोप में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है शिकायत एक महिला ग्राहक सेवा केंद्र संचालिका ने दर्ज कराई है जिसने आरोप लगाया है कि वीडियो हटाने के बदले उससे पहले 50 हजार रुपये की मांग की गई और बाद में दो लाख रुपये की अतिरिक्त रकम नहीं देने पर बदनाम करने की धमकी दी गई। पुलिस के अनुसार, मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है शिकायतकर्ता नेहा मिश्रा ने 25 जून को पुलिस में आवेदन देकर आरोप लगाया कि कुछ समय पहले सागर साहू और उसके साथी पुष्पराज सिंह आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने के बहाने उसके ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचे थे महिला का कहना है कि बातचीत को संदर्भ से हटाकर और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर वीडियो तैयार किया गया जिसे बाद में सोशल मीडिया पर समाचार के रूप में प्रसारित किया गया शिकायत में नेहा मिश्रा ने बताया कि वायरल वीडियो में उन्हें ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली के रूप में प्रस्तुत किया गया आरोप लगाया गया कि वह लोगों के अंगूठे के निशान का दुरुपयोग कर उनके बैंक खातों से पैसे निकालती हैं महिला ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि वीडियो के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा और ग्राहक सेवा केंद्र की साख भी प्रभावित हुई महिला का आरोप है कि 3 जून को यूट्यूबर्स ने वीडियो हटाने के बदले 50 हजार रुपये की मांग की। बदनामी के डर से उसने अपनी जमा पूंजी में से 35 हजार रुपये उन्हें दे दिए शिकायत के अनुसार रकम मिलने के बाद संबंधित वीडियो हटा लिया गया लेकिन कुछ समय बाद आरोपियों ने फिर दो लाख रुपये की मांग शुरू कर दी जब उसने अतिरिक्त रकम देने से इनकार किया तब कथित रूप से उसके खिलाफ तीन से अधिक नए वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए और लगातार बदनाम करने की धमकी दी गई पीड़िता का कहना है कि इन वीडियो के कारण समाज में उसकी छवि धूमिल हुई और उसे अपने ही ग्राहक सेवा केंद्र जाने में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है।

मॉब लिंचिंग केस में उम्रकैद के फैसले के बाद जज को मिली जान से मारने की धमकी

मीडिया ऑडीटर, सिवनी (निप्र)। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में मॉब लिंचिंग मामले में 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाने वाली एडीजे तबस्सुम खान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है धमकी भरे वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और साइबर एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक युवक खुलेआम धमकी देते हुए कहता दिखाई दे रहा है कि यदि 10 दिनों के भीतर सजा पाए सभी 'हिंदू भाइयों' को रिहा नहीं किया गया तो देश और प्रदेश में बड़े पैमाने पर हिंसा होगी वीडियो में उसने न्यायपालिका और संविधान के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। एक अन्य वायरल वीडियो में एक महिला ने भी एडीजे तबस्सुम खान के खिलाफ अभद्र और सांप्रदायिक टिप्पणियां करते हुए फैसले पर आपत्ति जताई महिला ने जज को निशाना बनाते हुए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और फैसले के परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। वीडियो वायरल होने के बाद गृह मंत्रालय की साइबर सेल ने आईटी एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है। वहीं सिवनी मालवा पुलिस ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है पुलिस का कहना है कि वीडियो बनाने और प्रसारित करने वालों की पहचान की जा रही है तथा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी गौरतलब है कि 12 जून को सिवनी मालवा स्थित अदालत ने वर्ष 2022 के चर्चित मॉब लिंचिंग मामले में 14 आरोपियों को हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और रास्ता रोकने सहित विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी यह मामला 3 अगस्त 2022 का है जब महाराष्ट्र के अमरावती जा रहे एक ट्रक को बराखड़ गांव के पास रोक लिया गया था ट्रक में लगभग 30 मवेशी मौजूद थे आरोप है कि ग्रामीणों और स्वयं को गो-रक्षक बताने वाले लोगों की भीड़ ने ट्रक में सवार तीन लोगों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था इस घटना में नाजिर अहमद की मौत हो गई थी, जबकि अन्य दो लोग घायल हो गए थे। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।

झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप भरत तिवारी का पोस्टर लगाकर एसपी कार्यालय पहुंचा युवक, निष्पक्ष जांच की मांग

मीडिया ऑडीटर,छतरपुर (निप्र)। जिले के गौरिहार थाना क्षेत्र के मनुरिया गांव निवासी रविकुमार अहिरवार ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया युवक ने अपने खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने और राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया विरोध जताने के लिए वह अपने शरीर पर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का पोस्टर चिपकाकर और हाथों में तख्तियां लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा इस दौरान उसने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई रविकुमार अहिरवार का आरोप है कि उसके खिलाफ लगातार राजनीतिक प्रभाव में झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं उसने दावा किया कि चंदला विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के बड़े भाई अशोक अहिरवार सहित कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में गौरिहार पुलिस उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। युवक का कहना है कि केवल वही नहीं बल्कि क्षेत्र के कई अन्य लोगों को भी इसी तरह प्रताड़ित किया जाता है एसपी को दिए गए आवेदन में रविकुमार ने बताया कि उसके खिलाफ पहले भी कई मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है उसका आरोप है कि 23 जून को एक बार फिर उसके खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया उसने कहा कि उसकी मां विधवा हैं और लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई से पूरा परिवार मानसिक तनाव में है युवक ने आवेदन में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा उसने यह भी लिखा कि उसे डर है कि कहीं उसकी स्थिति भी 'भरत तिवारी' जैसी न हो जाए इसी आशंका को व्यक्त करने के लिए उसने विरोध प्रदर्शन के दौरान भरत तिवारी का पोस्टर अपने शरीर पर लगाया रविकुमार ने यह भी बताया कि वह इस मामले में पहले भी थाना स्तर से लेकर क्षेत्रीय अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक कई बार आवेदन दे चुका है, लेकिन अब तक उसकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई उसका कहना है कि पिछले तीन दिनों से वह अपने घर भी नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसे और झूठे मामलों में फंसाए जाने तथा जान का खतरा बना हुआ है युवक ने 23 और 24 जून को दिए गए आवेदनों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज की जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी।

सांभर के बच्चे को दुलारना पड़ा भारी: वीडियो वायरल होने पर एसटीआर अधिकारी निलंबित, आचरण नियमों के उल्लंघन का आरोप

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के बोरी वन क्षेत्र में पदस्थ सहायक संचालक (एसडीओ) विनोद वर्मा को एक सांभर हिरण के बच्चे के साथ अनुचित व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में अधिकारी सांभर के बच्चे को सहलाते हुए और उसके सामने भोजन की प्लेट रखे दिखाई दे रहे थे वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और उन्हें निलंबित कर दिया। जानकारी के अनुसार यह वीडियो स्वयं विनोद वर्मा ने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया था वीडियो में वे जंगल क्षेत्र में एक सांभर के बच्चे के बेहद करीब नजर आते हैं वह उसे प्यार से सहला रहे हैं और उसके सामने पोहा से भरी प्लेट रखी हुई दिखाई देती है वीडियो वायरल होने के बाद वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों और आम नागरिकों ने इस व्यवहार पर सवाल उठाए उनका कहना था कि किसी भी वन अधिकारी द्वारा जंगली जानवरों के साथ इस प्रकार का संपर्क वन्यजीव संरक्षण के सिद्धांतों के विपरीत है मामले की जानकारी मिलते ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने पूरे प्रकरण की समीक्षा की प्रथम दृष्टया आचरण नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर उन्होंने विनोद वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि एक जिम्मेदार वन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार और आवास में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे ऐसे कृत्य न केवल सेवा नियमों के विरुद्ध हैं बल्कि वन्यजीव संरक्षण की भावना के भी विपरीत माने जाते हैं। निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि विनोद वर्मा का आचरण सरकारी अधिकारी के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता को दर्शाता है आदेश के अनुसार उनका व्यवहार मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है इसी आधार पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि जंगली जानवरों को मानव संपर्क और भोजन की आदत डालना उनके प्राकृतिक

व्यवहार के लिए नुकसानदायक हो सकता है इससे वन्यजीवों में मनुष्यों पर निर्भरता बढ़ने, प्राकृतिक भोजन खोजने की क्षमता प्रभावित होने तथा भविष्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका भी बढ़ सकती है इसी कारण वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होता है फिलहाल विभागीय स्तर पर मामले की आगे की जांच जारी ह जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी इस घटना ने वन अधिकारियों की जिम्मेदारियों और वन्यजीव संरक्षण संबंधी नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर गंभीर चर्चा छेड़ दी है।

अवैध खनन कार्रवाई के दौरान विवाद

वायरल वीडियो में खनिज निरीक्षक ने युवक को मारा थप्पड़, मामले ने पकड़ा नया मोड़

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ की गई कार्रवाई अब नए विवाद में घिर गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में खनिज निरीक्षक ऋषभ दीक्षित एक युवक को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं यह वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है क्योंकि इसी घटना के बाद खनिज निरीक्षक ने संबंधित युवक और उसके साथियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया था अब वीडियो वायरल होने के बाद घटना के दोनों पक्षों को लेकर सवाल उठने लगे हैं वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि खनिज निरीक्षक ऋषभ दीक्षित मौके पर मौजूद मंगल

लोधी नामक युवक से उसका मोबाइल फोन मांगते हैं दोनों के बीच कुछ देर बातचीत होती है जिसके बाद निरीक्षक अचानक युवक को थप्पड़ मार देते हैं थप्पड़ लगते ही मौके का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की तथा तीखी बहस शुरू हो जाती है आसपास मौजूद लोग भी घटनास्थल पर एकत्र हो जाते हैं जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन जाती है जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला कुछ दिन पहले की उस कार्रवाई से जुड़ा है जब खनिज विभाग की टीम पिछोर क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ अभियान चला रही थी इसी दौरान अधिकारियों ने पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोककर जांच की जांच में चालक के पास खनिज परिवहन से संबंधित वैध रॉयल्टी और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए इसके बाद खनिज निरीक्षक ने नियमानुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया बताया गया कि जब जब्त वाहन को पुलिस की मौजूदगी में थाने ले जाया जा रहा था उसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया इसी दौरान खनिज विभाग की टीम और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी हो गई जो बाद में धक्का-मुक्की में बदल गई घटना के बाद खनिज निरीक्षक ऋषभ दीक्षित ने पिछोर थाने में शिकायत दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया गया कि मंगल लोधी और अन्य लोगों ने सरकारी कार्रवाई में बाधा डाली पुलिस और विभागीय कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा जब्त वाहन को छुड़ाने का प्रयास किया पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अब सामने आए नए वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को एक अलग दिशा दे दी है वीडियो में निरीक्षक द्वारा युवक को थप्पड़ मारते हुए देखे जाने के बाद सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार: पोहरी एसडीएम के रीडर की पत्नी की मौत, चार घायल

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले में शुक्रवार देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में पोहरी एसडीएम कार्यालय के रीडर श्याम सिंह दोहरे की पत्नी मनीषा दोहरे (40) की मौत हो गई जबकि श्याम सिंह दोहरे सहित चार अन्य लोग घायल हो गए हादसा रात करीब 12:30 बजे शिवपुरी-झिरी मार्ग पर मुद्गल पेट्रोल पंप के पास हुआ जब उनकी कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से पीछे से टकरा गई जानकारी के अनुसारदश्याम सिंह दोहरे का हाल ही में भिंड स्थानांतरण हुआ था शुक्रवार को जिला मुख्यालय शिवपुरी से कार्यमुक्त होने के बाद वे कार से पोहरी लौट रहे थे कार में उनकी पत्नी मनीषा दोहरे के अलावा एक

परिचित शिक्षक, उनकी पत्नी और उनका बच्चा भी सवार थे। बताया जा रहा है कि शिवपुरी-पोहरी मुख्य मार्ग की खराब स्थिति के कारण उन्होंने झिरी मार्ग से जाने का निर्णय लिया इसी दौरान मुद्गल पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी कार की जोरदार टक्कर हो गई टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

छत्तीसगढ़ के 15 से अधिक सांसद-विधायकों पर आपराधिक मामले लंबित, हाईकोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में 20 से ज्यादा केसों का उल्लेख

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को लेकर हाईकोर्ट द्वारा जारी मई 2026 की स्टेटस रिपोर्ट ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 15 से अधिक सांसद, विधायक और पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 20 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई विभिन्न अदालतों में जारी है इन मामलों की नियमित मॉनिटरिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष अदालतों के माध्यम से की जा रही है ताकि सुनवाई में अनावश्यक देरी न हो

रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक कवासी लखमा, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित कई वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के नाम शामिल हैं इन सभी मामलों की सुनवाई संबंधित न्यायालयों में निर्धारित तिथियों पर जारी है। रायपुर स्थित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैलाश मुरारका और विजय भाटिया के खिलाफ वर्ष 2018 में दर्ज आपराधिक प्रकरण की सुनवाई चल रही है इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), 469 (जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत आरोप लगाए गए हैं इस मामले की सुनवाई के लिए 19 जून 2026 की तारीख निर्धारित की गई थी इसी प्रकार रायपुर की प्रथम जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय में विधायक कवासी लखमा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामले की सुनवाई जारी है इसके अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कवासी लखमा और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भी न्यायालय में कार्यवाही चल रही है। जांजगीर-चांपा जिले में बालेश्वर साहू, वेदप्रकाश साहू और गौतम राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी और मारपीट से जुड़े मामलों की सुनवाई जिला न्यायालय में चल रही है वहीं कवर्धा में अशोक कुमार साहू और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है गरियाबंद जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में भाजपा के पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी और गोवर्धन मांझी के खिलाफ रास्ता रोकने और बलवा से जुड़े मामलों की सुनवाई जारी है इसी जिले में रोहित साहू के खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग मामलों में भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है जिनमें से एक मामला हाल ही में दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। राजनांदगांव के विशेष न्यायालय में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और मोहम्मद खालिद के खिलाफ निवेशकों से कथित धोखाधड़ी से जुड़े छह मामले लंबित हैं इनमें से तीन मामलों की सुनवाई पर वर्ष 2021 से हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है।

सीहोर में किसान की फसल पर चलाया ट्रैक्टर

रोकने पर बोले- कोई पटवारी नहीं आएगा, ट्रैक्टर यहीं से निकलेगा, वीडियो सामने आया

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले के अहमदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपलखेड़ा गांव में एक किसान की बोई हुई फसल को ट्रैक्टर से रौंदकर नष्ट करने का मामला सामने आया है। गांव के ही पांच लोगों ने किसान के खेत में जबरन ट्रैक्टर चला दिया और जब पीड़ित पक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। गुंडागर्दी की इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ही खेत में एक साथ कई ट्रैक्टर, कल्टीवेटर और बोनी मशीन लेकर कुछ लोग जबरन जुताई कर रहे हैं। इस दौरान पीड़ित पक्ष के लोग जब ट्रैक्टर को रोकने आगे आते हैं, तो आरोपी धक्का-मुक्की करने लगते हैं। वीडियो में एक युवक विरोध जताने के लिए गाड़ी के आगे जमीन पर बैठ जाता है, जिसे देखकर दबंग उकसाते हुए कहते हैं, 'ले मार, जो होना है हो जाने दे... तू उठ जा गाड़ी के सामने से, ट्रैक्टर तो यहीं से निकलेगा।' जब पीड़ित कहता है कि फैसला पटवारी की मौजूदगी में होगा, तो आरोपी दादागिरी दिखाते हुए कहते हैं, 'कोई पटवारी नहीं आएगा, ट्रैक्टर यहीं चलेगा।' इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और मारपीट की नौबत आ जाती है।

आपसी रंजिश में 5 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम: अहमदपुर थाने में दी गई शिकायत के अनुसार, पीपलखेड़ा निवासी किसान मानसिंह ने अपनी कृषि भूमि पर फसल बोई थी। उनका आरोप है कि गांव के राजू, महेंद्र, चंदरसिंह, अरविंद और योगेंद्र ने आपसी रंजिश के चलते जानबूझकर उनकी बोई हुई फसल के बीच से ट्रैक्टर निकाल दिया। इससे उनकी खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। किसान का कहना है कि विरोध करने पर आरोपियों ने अपशब्द कहे और भविष्य में भी खेत में नुकसान करने की धमकी दी।

अहमदपुर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच: पीड़ित मानसिंह ने अहमदपुर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच, फसल के नुकसान के मुआवजे और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने किसान का आवेदन स्वीकार कर मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। वीडियो फुटेज के आधार पर भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

छतरपुर के स्कूल में फटा बम, 2 छात्र गंभीर: लावारिस चीज से खेल रहे थे बच्चे, बारात के छूटे पटाखे पर शक

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर जिले के चंदला थाना क्षेत्र स्थित सिलगांव के प्राथमिक विद्यालय में एक संदिग्ध पटाखा बम फटने से दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सोमवार, 24 जून की है, जब बच्चे स्कूल परिसर में खेल रहे थे। धमाके में घायल दोनों बच्चों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार, 8 वर्षीय कालका दीन (पिता कल्लू राजपूत) और उसका साथी राहुल (पिता इंद्र बहादुर राजपूत) सोमवार को स्कूल पहुंचे थे। खेलते समय उन्हें स्कूल परिसर में एक लावारिस बम जैसी वस्तु दिखाई दी। उत्सुकतावश दोनों बच्चे उसे उठाकर स्कूल की एक जर्जर इमारत की ओर ले गए। वहां जैसे ही उन्होंने उस वस्तु से छेड़छाड़ की, अचानक जोरदार धमाका हो गया और दोनों बुरी तरह घायल हो गए।परिजनों का आरोप- स्कूल में रुकी थी बारात, वहीं छूटा बम इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि 22 जून को स्कूल परिसर में एक बारात रुकी थी।

खेत से जंगल ले जाकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार,राजगढ़ में एक हफ्ते तक धमकी से डरी रही पीड़िता, फिर थाने पहुंची

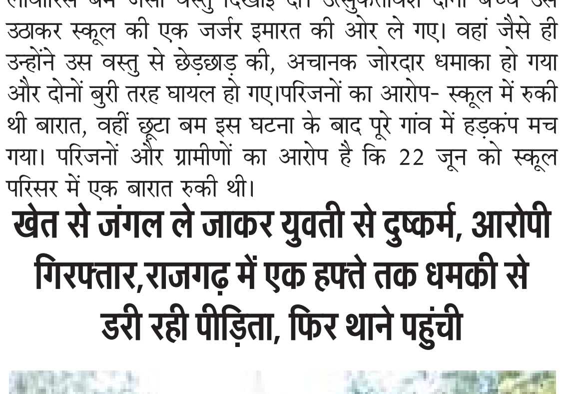

मीडिया ऑडीटर, राजगढ़ (निप्र)। राजगढ़ जिले के माचलपुर थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना एक सप्ताह पहले की बताई जा रही है, जबकि शुक्रवार रात पीड़िता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि 19 जून की सुबह करीब 11 बजे वह अपने खेत के पास मौजूद थी। इसी दौरान गांव का रहने वाला आरोपी उसे जबरन जंगल की ओर ले गया। वहां उसने युवती की इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया और किसी को घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दी। भय के कारण पीड़िता तत्काल शिकायत नहीं कर सकी। पीड़िता की शिकायत पर माचलपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। थाना प्रभारी आदित्य सोनी ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।

20 फीट ऊंचा ताजिया तार से टकराया, 3 की मौत

रतलाम में 10 से ज्यादा झुलसे, 5 गंभीर, मुहर्रम जुलूस में 200 लोग थे शामिल

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)।मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में गुरुवार रात ताजिया हाईटेंशन बिजली लाइन से टकरा गया। करंट की चपेट में 10 से अधिक लोग आ गए। इनमें 3 की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर है। सभी को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना पिपलोदा के हतनारा गांव की है।

जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान रशीद खान, सद्दू हुसैन और अरबाज खान के रूप में हुई है। हालांकि अरबाज के परिजन उसे अस्पताल से कहीं और ले गए। इस कारण प्रशासन ने 2 मौतों की पुष्टि की है, जबकि ड्यूटी डॉक्टर रविंद्र सोलंकी ने 3 मौतों की पुष्टि की है।

घायलों का मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज: मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों में अनास पिता अकरम (16), मोइन शाह पिता इश्क शाह (35), रहीम खान, अख्तियार खान, इरफान, शाहरुख, शकील, रईस, मोहम्मद और वहीद शामिल हैं। वहीं इब्राहिम पिता हनीफ को रतलाम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।लाइनमैन को किया निलंबित हतनारा में पदस्थ लाइनमैन घनश्याम गिर (पिता भगवान गिर) को मुहर्रम जुलूस के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जावरा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी, रतलाम ने समरथ मकवाना और गोबीलाल (बिजली श्रमिक) को भी कार्य में लापरवाही के चलते सेवा से पृथक करने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने घायलों से हालचाल पूछा

शुक्रवार सुबह कलेक्टर मिशा सिंह और शहर एसडीएम तरुण जैन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और हादसे में घायल भर्ती लोगों का हालचाल जाना। चिकित्सकों ने बताया कि अस्पताल में भर्ती तीनों घायलों की हालत अब खतरे से बाहर है। हादसे में तीन की मौत हुई है। अरबाज नमक मृतक को उसके परिवार वाले रात को गांव लेकर चले गए थे। जब प्रशासन को पता चला तो रात को उसका शव लेकर रतलाम मेडिकल कॉलेज लाया गया।

हादसे के वक्त का वीडियो भी आया सामने

घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें करंट लगने के बाद जुलूस में अफरा-तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग चीखते-चिल्लाते नजर आ रहे हैं, जबकि कई लोग जमीन पर पड़े दिख रहे हैं। आसपास के लोग घायलों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।

ड्यूटी डॉक्टर बोले- तीन लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था

रतलाम मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात डॉ. रविंद्र सोलंकी ने बताया कि तीन लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी। उन्हें मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। 3 मृतकों में से 2 के परिजन औपचारिक कागजी प्रक्रिया पूरी किए बिना उन्हें अपने साथ ले गए। उन्हें बता दिया गया था कि उनकी धड़कनें बंद हो चुकी हैं।

एएसपी बोले- हाईटेंशन लाइन से टकराने के बाद हुआ हादसा

रतलाम एएसपी राकेश पंद्रो ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि हाईटेंशन लाइन की ऊंचाई और सुरक्षा मानकों में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई।हादसे में तीन लोगों की मौत, 5 घायलों का इलाज जारी।

करीब 200 लोग जुलूस में थे शामिल: प्रत्यक्षदर्शी इमामुद्दीन मंसूरी ने बताया कि मुहर्रम के अवसर पर हतनारा गांव में ताजिया जुलूस निकाला जा रहा था।

जुलूस में करीब 200 लोग शामिल थे। इसी दौरान लगभग 20 फीट ऊंचाई पर गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन से ताजिया टकरा गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, बिजली लाइन काफी नीचे थी।

हत्या के बाद फरार 10 हजार का इनामी पकड़ा

मृतक न्यौता खाकर गांव लौट रहा था, आरोपियों ने घेरकर की थी हत्या

मीडिया ऑडीटर, भिंड (निप्र)। भिंड के मेहगांव थाना पुलिस ने कैंथोला गांव में हुए चर्चित हत्याकांड के एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया है। इस मामले में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

पुलिस के अनुसार, 20 अप्रैल 2026 को कैंथोला गांव निवासी गिर्राज गुर्जर गांव में न्यौता (भोज) खाकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के पास आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी, डंडों व बंदूक से हमला कर दिया। मारपीट के बाद गिर्राज गुर्जर को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में मेहगांव थाना पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।

जांच में पुलिस ने आसवीर गुर्जर, रायभान गुर्जर, अमरसिंह गुर्जर, नीतू गुर्जर और साहब सिंह गुर्जर को आरोपी बनाया था। घटना के बाद पुलिस ने पहले आसवीर गुर्जर, नीतू गुर्जर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को पुलिस ने 10 हजार रुपये के इनामी रायभान गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल तथा एसडीओपी मेहगांव संजय कोच्छा के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर मेहगांव थाना पुलिस ने रायभान गुर्जर को उसके घर के बाहर से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है।

इस हत्याकांड में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि साहब सिंह गुर्जर अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

सराहनीय भूमिका: कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक महेश शर्मा, प्रधान आरक्षक प्रदीप पचौरी, आरक्षक दिनेश मुदगल एवं चालक आरक्षक शिवकुमार शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अशोकनगर में वाहन की टक्कर से युवक की मौत, सिर में लगी गंभीर चोट, हैदर गांव में हुआ हादसा

मीडिया ऑडीटर, अशोकनगर (निप्र)। अशोकनगर जिले के देहात थाना क्षेत्र के हैदर गांव में शुक्रवार रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हैदर गांव निवासी 35 वर्षीय जसमन पुत्र कमला अहिरवार के रूप में हुई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार रात करीब साढ़े 8 बजे हुआ। परिजनों ने बताया कि जसमन का घर गांव से कुछ दूरी पर है। वह रात के समय गांव से अपनी बाइक पर घर लौट रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। टक्कर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने जसमन को सड़क पर पड़ा देखा और तुरंत उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। जब परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक जसमन की शरीर की हलचल थम गई थी। घटना की सूचना देहात पुलिस को दी गई। देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जसमन की मौत की पुष्टि की। शव को रात भर पोस्टमार्टम गृह में रखा गया और शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

खेत पर जाते परिवार की बाइक में ट्रक की टक्कर

छिंदवाड़ा में मासूम की मौत, दादा और पिता की हालत खराब,मक्का बोने जा रहे थे

मीडिया ऑडीटर, छिंदवाड़ा (निप्र)। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत दीघावानी गांव के पास शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। राशन से भरे एक ओवरलोडेड ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक मासूम बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता और दादा गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, दीघावानी निवासी संत कुमार अपने पिता चतरु और छोटे बच्चे कार्तिक खसरे के साथ बाइक से खेत में मक्का बोनी करने जा रहे थे। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, तभी अमरवाड़ा की ओर से आ रहे ट्रक (MP28 ZD 6193) ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि मासूम कार्तिक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं संत कुमार और उनके पिता चतरु गंभीर रूप से घायल हो गए।

अस्पताल में भर्ती, छिंदवाड़ा रेफर: हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को तत्काल अमरवाड़ा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए घायल पिता-पुत्र को छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

पुलिस ने मृतक बालक का पोस्टमार्टम कराकर मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है।

ओवरलोडिंग पर फिर उठे सवाल: स्थानीय लोगों ने एक बार फिर राशन ढोने वाले अन्नदूत वाहनों की ओवरलोडिंग पर सवाल उठाए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से ऐसे वाहन लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

नौकरी से निकालने पर कूरियर ऑफिस से 1.5 लाख लूट

नीमच में विरोध करने पर एक कर्मचारी को मारे चाकू

मीडिया ऑडीटर, नीमच (निप्र)। नीमच पुलिस ने उदय विहार इलाके में स्थित 'डेल्हीवरी कूरियर कंपनी' के दफ्तर में हुई चाकूबाजी और डेढ़ लाख की सनसनीखेज लूट 36 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी राजेश व्यास ने शुक्रवार शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी डकैती का खुलासा किया।

नौकरी से निकाले जाने का बदला लेने के लिए रची साजिश: हैरानी की बात यह है कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कूरियर कंपनी का ही पूर्व कर्मचारी इस्लाम मोहम्मद निकला। इस्लाम को कुछ समय पहले कंपनी ने काम से निकाल दिया था। उसे दफ्तर में कैश कलेक्शन के समय और तौर-तरीकों की पूरी जानकारी थी।

नौकरी से निकाले जाने का बदला लेने के लिए उसने मंदसौर के अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूट की यह पूरी प्लानिंग की। शातिर इस्लाम वारदात से ठीक 15 दिन पहले ही दोबारा झांसा देकर काम पर लौटा था।

ऑफिस में अकेले पाकर कूरियर कर्मी पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार यह वारदात 23 जून की रात करीब 9:20 बजे हुई थी। कूरियर कर्मी सूरज नाथ ऑफिस में अकेला काम कर रहा था, तभी एक बाइक पर सवार चार बदमाश अंदर घुसे। बदमाशों ने सूरज की गर्दन दबोचकर उसकी कनपटी पर चाकू अड़ा दिया और उसे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगे। जब सूरज ने कैश काउंटर से पैसे समेट रहे बदमाशों का विरोध किया और शोर मचाया, तो आरोपी सोहेल मंसूरी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में सूरज के हाथ और दोनों कंधों पर गंभीर चोटें आईं और बदमाश डेढ़ लाख रुपए लेकर फरार हो गए।

खेत में गाड़े थे चोरी के 2.30 लाख, पड़ोसी गिरफ्तार,खंडवा में किसान के घर से चुराए थे जमीन के पैसे, शराब का आदी है आरोपी

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। खंडवा जिले के धनगांव थाना क्षेत्र के सालई गांव में पुलिस ने 2.30 लाख रुपए की चोरी का पर्दाफाश किया है। एक किसान के घर से यह रकम उसके ही पड़ोसी किसान ने चुराई थी। आरोपी ने चोरी के बाद पूरी रकम अपने खेत में सागवान के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दी थी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जमीन खुदवाकर पूरा कैश बरामद कर लिया है।

धनगांव टीआई गंगाप्रसाद वर्मा के अनुसार, सालई गांव निवासी 60 वर्षीय गेंदालाल मोरे 17 जून को परिवार सहित एक शादी समारोह में गए थे। उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए अपनी एक एकड़ जमीन बेची थी।

जमीन की बिक्री से मिले पैसों में से 2 लाख 30 हजार रुपए उन्होंने अपनी अलमारी में रखे थे। 21 जून को जब परिवार वापस लौटा, तो घर का ताला टूटा मिला और अलमारी से नकदी गायब थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

लगातार शराब पीने से हुआ शक, सख्ती पर कबूला जुर्म: पुलिस ने थाने से 30 किलोमीटर दूर स्थित सालई गांव में मुखबिरों को सक्रिय किया। जांच के दौरान पुलिस को गेंदालाल के पड़ोसी किसान रवींद्र गढ़वाल पर शक हुआ, जिसका खेत पीड़ित के खेत से लगा हुआ है।

पुलिस को जानकारी मिली कि रवींद्र शराब का आदी है और परिवार ने उसे पैसे देना बंद कर दिया था। इसके बावजूद वह दो दिन से लगातार शराब पी रहा था। पुलिस ने इसी आधार पर उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर खेत में गड़े रुपए भी बरामद कर लिए गए।

पीड़ित से ज्यादा अमीर है आरोपी, लत ने बनाया चोर: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रवींद्र का पीड़ित के घर नियमित आना-जाना था। उसे पता था कि गेंदालाल ने हाल ही में जमीन बेची है और उसने पैसे अलमारी में रखते हुए देखे थे। इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने सूने घर में सेंधमारी की।

हैरानी की बात यह है कि आरोपी का परिवार आर्थिक रूप से पीड़ित किसान से काफी बेहतर स्थिति में है। गेंदालाल के पास केवल तीन एकड़ जमीन है, जबकि आरोपी के परिवार के पास करीब छह एकड़ कृषि भूमि है। केवल शराब की लत ने उसे चोरी जैसा अपराध करने पर मजबूर कर दिया।

भारत बनाम आयरलैंड: सिर्फ 2 टी20 मुकाबलों में लुटाए 125 रन

प्रसिद्ध कृष्णा के नाम पर जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

बेलफास्ट , एजेंसी। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा लगातार 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सर्वाधिक 125 रन लुटाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने शुक्रवार को आयरलैंड के विरुद्ध टी20 सीरीज के पहले मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें बगैर कोई विकेट हासिल किए 57 रन लुटा दिए। इससे पहले उन्होंने 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 4 ओवरों में 68 रन दिए थे। उस मैच में भी कृष्णा कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने 28 नवंबर 2023 को टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, तब से लेकर अब तक उन्होंने 6 मुकाबलों में कुल 144 गेंदें फेंकी हैं, जिसमें 277 रन लुटाए हैं। इस दौरान उन्हें 8 विकेट हाथ लगे। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर के शुरुआती दो मुकाबले आयरलैंड के खिलाफ खेले थे। पहले मैच में उन्होंने 32 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। अगले मुकाबले में 29 रन देकर 2 विकेट निकाले। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के तीन मुकाबलों में उन्होंने कुल 4 विकेट हासिल किए। विशाखापत्तनम में प्रसिद्ध कृष्णा ने 50 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और फिर तिरुवनंतपुरम में 41 रन देकर 3 विकेट प्राप्त किए, लेकिन गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में 68 रन लुटाने के बावजूद कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा लंबे समय तक टी20 टीम का हिस्सा नहीं रहे। अब जब कृष्णा को फिर से भारतीय टीम में शामिल किया गया, तो एक बार फिर से उन्होंने भारतीय फैंस को निराश किया है। सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में जारी इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आयरलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए। इस टीम ने 51 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से गैरेथ डेलानी ने कप्तान लोर्कन टकर के साथ पांचवें विकेट के लिए 44 गेंदों में 64 रन की साझेदारी की। टकर 36 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद डेलानी (49) ने जॉर्ज डॉकरेल (19) के साथ छठे विकेट के लिए सिर्फ 16 गेंदों में 49 रन जोड़कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

भारत की तरफ से हर्षित राणा ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट निकाले। एक विकेट शिवम दुबे के हाथ लगा।

आखिरी ग्रुप मैच में नहीं दिखेंगे लियोनेल मेसी

कोच स्कालोनी ने बताई बड़ी वजह

नई दिल्ली , एजेंसी। विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण में लगातार दो शानदार जीत दर्ज कर अर्जेंटीना ने नॉकआउट चरण में अपनी जगह लगभग सुरक्षित कर ली है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट अब अपने स्टार खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसी रणनीति के तहत कप्तान लियोनेल मेसी को जॉर्डन के खिलाफ आखिरी ग्रुप मुकाबले में शुरुआती एकादश से बाहर रखने का फैसला किया गया है। हालांकि मेसी पूरी तरह मैच से बाहर नहीं होंगे और दूसरे हाफ में बतौर सब्स्टीट्यूट मैदान पर उतर सकते हैं।

जॉर्डन के खिलाफ बेंच पर बैठेंगे मेसी

अर्जेंटीना के मुख्य कोच लियोनेल स्कालोनी ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि लियोनेल मेसी शनिवार को जॉर्डन के खिलाफ शुरुआती प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे। स्कालोनी ने कहा, लियोनेल मेसी इस मुकाबले की शुरुआत बेंच से करेंगे। वह बाद में बतौर सब्स्टीट्यूट मैदान पर उतरेंगे। अंतिम टीम की घोषणा मैच वाले दिन की जाएगी।

नॉकआउट से पहले खिलाड़ियों को आराम देने की रणनीति स्कालोनी का मानना है कि टीम पहले ही राउंड ऑफ 32 में जगह बना चुकी है, इसलिए नॉकआउट मुकाबलों से पहले प्रमुख खिलाड़ियों को आराम देना जरूरी है। साथ ही, बेंच पर मौजूद खिलाड़ियों को भी खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। कोच का मानना है कि लंबे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की फिटनेस सबसे अहम होती है और मेसी जैसे अनुभवी खिलाड़ी को ताजा रखना टीम की प्राथमिकता है।

शानदार फॉर्म में है अर्जेंटीना

डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने ग्रुप-जे में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने पहले मुकाबले में अल्जीरिया को हराया, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रिया को मात देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इन दोनों जीत के साथ अर्जेंटीना सात अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष स्थान पर है और पहले ही राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अब जॉर्डन के खिलाफ मुकाबला टीम के लिए केवल ग्रुप चरण का औपचारिक मैच माना जा रहा है।

2026 विश्व कप में भी चमक रहे हैं मेसी

38 वर्षीय लियोनेल मेसी इस विश्व कप में भी अर्जेंटीना के सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। अनुभव और नेतृत्व के दम पर वह टीम को लगातार मजबूती दे रहे हैं। हालांकि स्कालोनी और टीम प्रबंधन जानते हैं कि नॉकआउट चरण में मेसी की फिटनेस सबसे बड़ी ताकत होगी। इसी वजह से उनके कार्यभार को सावधानी से मैनेज किया जा रहा है, ताकि वह बड़े मुकाबलों में पूरी तरह फिट रहें।

अब नॉकआउट पर अर्जेंटीना की नजर

जॉर्डन के खिलाफ मुकाबले के बाद अर्जेंटीना का पूरा फोकस राउंड ऑफ 32 पर होगा। टीम लगातार तीसरी जीत के साथ नॉकआउट में प्रवेश करना चाहेगी, जबकि स्कालोनी उम्मीद करेंगे कि उनके सभी प्रमुख खिलाड़ी अगले दौर से पहले पूरी तरह फिट और तरोताजा रहें।

विंबलडन: ओपन एरा में एकल का खिताब जीतने वाले सबसे युवा और पुरुष खिलाड़ी कौन हैं

नई दिल्ली , एजेंसी। विंबलडन 2026 की शुरुआत 29 जून से हो रही है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हर पुरुष और महिला खिलाड़ी का सपना खिताब जीतना होता है। इस बार महिला एकल में जीत की प्रबल दावेदार आर्यना सबालेंका और इगा स्विएटेक हैं, तो पुरुष एकल का खिताब जीतने के प्रबल दावेदार में जानिक सिनर, नोवाक जोकोविच का नाम प्रमुख है। विंबलडन का इतिहास बहुत पुराना है। 1968 से ओपन एरा की शुरुआत हुई थी। आइए जानते हैं कि ओपन एरा शुरू होने के बाद किस खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में विंबलडन का खिताब जीता है। विंबलडन में ओपन एरा शुरू होने के बाद पुरुष एकल का खिताब सबसे कम उम्र में जर्मनी के बोरिस बेकर ने जीता था। बेकर ने 1985 में 17 साल, 227 दिन की उम्र में विंबलडन का खिताब जीता था। वह ओपन एरा में इस प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम को जीतने वाले सबसे युवा क्रिकेटर हैं। बेकर ने 18 साल, 7 महीने की उम्र में 1986 में भी विंबलडन का खिताब जीता था। बेकर ने अपने पेशेवर करियर में 6 ग्रैंड स्लैम जीते थे। बेकर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन (1991, 1996), विंबलडन (1985, 1986 और 1989), और यूएस ओपन (1989) जीता था। वह अपने करियर में कभी भी फ्रेंच ओपन नहीं जीत सके। इस वजह से उनका करियर ग्रैंड स्लैम पूरा नहीं हो सका। वहीं, ओपन एरा में महिला एकल विंबलडन का खिताब जीतने वाली सबसे युवा महिला का रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के नाम है। हिंगिस ने 16 साल, 278 दिन की उम्र में 1997 में विंबलडन जीता था। दूसरी सबसे युवा महिला रूस की मारिया शारापोवा हैं। शारापोवा ने 2004 में 17 साल, 2 महीने की उम्र में खिताब जीता था। मार्टिना हिंगिस ने करियर में पांच एकल ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन (1997, 1998, 1999), विंबलडन (1997) और यूएस ओपन (1997) जीता है। डबल्स में हिंगिस का रिकॉर्ड बेहतरीन है। उन्होंने 13 खिताब जीते हैं। इसमें चारों ग्रैंड स्लैम शामिल हैं। सर्वाधिक 5 बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है।

फीफा वर्ल्ड कप: स्वीडन के लिए बड़ा झटका

चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए इसाक हिएन

वैंकूवर , एजेंसी। स्वीडन को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस के खिलाफ नॉकआउट मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार डिफेंडर इसाक हिएन हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। 27 साल के इस खिलाड़ी को गुरुवार को जापान के साथ स्वीडन के 1-1 के ड्रॉ मैच में चोट लगी थी। इस नतीजे के साथ ही स्वीडन ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की की और तीसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ 8 टीमों में शामिल रहते हुए नॉकआउट स्टेज का टिकट कटाया। स्वीडिश फुटबॉल एसोसिएशन (एसवीएफएफ) ने शनिवार को इसाक को लगी इस चोट की पुष्टि की और कहा कि वह वर्ल्ड कप में आगे कोई हिस्सा नहीं ले पाएंगे और रिहैबिलिटेशन शुरू करने के लिए अपने क्लब लौटेंगे। नेशनल टीम के डॉक्टर जोनास वर्नर ने एक बयान में कहा, इसाक के बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई है कि वह वर्ल्ड कप में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वह अपने क्लब लौटेंगे, और चोट का मतलब है कि वह कुछ समय के लिए फुटबॉल से दूर रहेंगे। स्वीडन अब फ्रांस के खिलाफ अपने नॉकआउट मैच में अपने एक खास डिफेंडर के बिना उतरेगा, जिसके कारण टीम को इस अहम मैच में अपनी बैकलाइन में बदलाव करना पड़ेगा। स्वीडन के कोच ग्राहम पॉटर ने हिएन के लिए निराशा जताई और डिफेंडर के ठीक होने तक टीम का पूरा सपोर्ट देने का वादा किया। पॉटर ने कहा, इस तरह चोट के साथ वर्ल्ड कप खत्म करना बहुत दुख की बात है और हम उन्हें हर मुमकिन तरीके से सपोर्ट करेंगे। यह उनके लिए दुख की बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह और मजबूत होकर वापस आएंगे।

फर्नांडो का अर्धशतक

भारतीय टीम के खिलाफ दूसरे दिन श्रीलंका-ए की वापसी

गाल , एजेंसी। श्रीलंका-ए ने भारत-ए के खिलाफ अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शानदार वापसी की है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 452/6 के स्कोर पर घोषित की, जिसके बाद दूसरे दिन की समाप्ति तक मेजबान टीम ने 2 विकेट खोकर 113 रन बना लिए है। फिलहाल श्रीलंकाई टीम भारत-ए की पहली पारी से 339 रन पीछे है। गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को आयुष पांडे और साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 23 ओवरों में 82 रन जोड़े। आयुष 64 गेंदों में 3 चौकों के साथ 25 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद साई सुदर्शन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ (22) के साथ तीसरे विकेट के लिए 90 रन जुटाए, जबकि ध्रुव जुरेल के साथ चौथे विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी की। सुदर्शन 175 गेंदों में 19 चौकों के साथ 132 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 217 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से ध्रुव जुरेल ने टीम को मजबूती दी। शेख रशीद के साथ पांचवें विकेट के लिए 136 रन जोड़ने के बाद उन्होंने हर्ष दुबे के साथ छठे विकेट के लिए 86 रन जुटाए। रशीद 5 चौकों के साथ 63 रन बनाकर आउट हुए, जबकि दुबे ने 30 रन का योगदान दिया। जुरेल 215 गेंदों में 14 बाउंड्री के साथ 141 रन बनाकर नाबाद रहे। विपक्षी खेमे से चमिका गुणासेकरा ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि दिलुम सुदीरा ने 2 विकेट अपने नाम किए। इसके जवाब में श्रीलंका ने दिन की समाप्ति तक 31 ओवरों का सामना किया। महज 13 के स्कोर पर टीम को निरोशन डिकवेला (10) के रूप में बड़ा झटका लग गया था। इसके बाद 38 के कुल योग पर टीम ने पवनथा वीरासिंघे (11) का विकेट भी खो दिया था।

तीसरी एशियाई रिले चैंपियनशिप-2027 का ध्वज चंडीगढ़ को प्राप्त, प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा शहर

चंडीगढ़ , एजेंसी। तीसरी एशियाई रिले चैम्पियनशिप-2027 का ध्वज आज पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को यूटी सचिवालय में भेंट किया गया। यह ध्वज चीन के शाओशिंग में आयोजित दूसरी एशियाई रिले चैम्पियनशिप-2026 के समापन समारोह के दौरान औपचारिक रूप से चंडीगढ़ को सौंपा गया था। इसे चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व करने वाले चंडीगढ़ प्रशासन के खेल निदेशक सौरभ कुमार अरोड़ा चंडीगढ़ लेकर आए। इस अवसर पर चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद, पंजाब के राज्यपाल के अपर मुख्य सचि विवेक प्रताप सिंह, खेल सचिव प्रेरणा पुरी, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के सदस्य, चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रशासक ने इसे चंडीगढ़ के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि शहर को इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय चैम्पियनशिप के अगले संस्करण की मेजबानी का अवसर मिलना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1989 में आयोजित एशियाई रोइंग चैम्पियनशिप के बाद यह चंडीगढ़ में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन होगा और इससे अंतरराष्ट्रीय खेलों के उभरते केंद्र के रूप में शहर की पहचान और मजबूत होगी।

प्रशासक ने बताया कि चैम्पियनशिप का आयोजन सेक्टर-7 स्थित खेल परिसर में किया जाएगा, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन सभी हितधारकों के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रहा है तथा विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना, सुरक्षा प्रबंध और सुचारु आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

कटारिया ने कहा कि इस स्तर की अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिप की मेजबानी से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी, एथलेटिक्स में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय खिलाड़ियों को एशिया की शीर्ष रिले टीमों का प्रदर्शन देखने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगा और अंतरराष्ट्रीय मंच पर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की समृद्ध संस्कृति एवं विरासत को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।

एशियाई रिले चैम्पियनशिप एशियाई एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता है, जिसमें पुरुष, महिला और मिश्रित वर्ग की रिले स्पर्धाओं, जिनमें 4म100 मीटर और 4म400 मीटर दौड़ शामिल हैं, में एशिया की अग्रणी रिले टीमें भाग लेती हैं।

वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला डेब्यू का मौका

कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कहा

बेलफास्ट, एजेंसी। भारत और आयरलैंड के बीच 2 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेला जा रहा है। बतौर भारतीय कप्तान अपना पहला मैच खेल रहे श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में बाएं हाथ के करिश्माई और विस्फोटक बल्लेबाज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। सूर्यवंशी को अंतिम-11 में जगह नहीं मिल सकी है। वैभव को भारतीय टीम में डेब्यू के लिए अब कम-से-कम अगले मैच तक का इंतजार करना होगा। वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं देने के सवाल पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, वैभव एक शानदार खिलाड़ी है, लेकिन बदकिस्मती से नहीं खेल रहा है। हमारी टीम में अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इंडिया के लिए पिछली कुछ सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि हम अपने उन ज्यादातर क्रिकेटरों का समर्थन कर रहे हैं, जो पूरे सीजन में बहुत शानदार रहे हैं। पहले टी20 में मौका न मिलना वैभव सूर्यवंशी के लिए निराशाजनक हो सकता है। डेब्यू कैप मिलते ही वह भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाते। वैभव इस मैच में सचिन तेंदुलकर का लगभग 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। हालांकि, वैभव के पास इस रिकॉर्ड को

तोड़ने के लिए आगे मौके निश्चित रूप से मिलेंगे। वैभव ने पिछले 1 साल में हर स्तर पर और जहां भी मौके मिले हैं, शानदार प्रदर्शन किया है। आईपीएल 2025 से चर्चा में आए वैभव ने पिछले एक साल में इंडिया ए और इंडिया-19 के लिए दमदार पारियां खेली हैं और देश को अहम खिताब दिलाए हैं। आईपीएल 2026 में उनके दमदार प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टीम में जगह दिलायी है। आईपीएल 2026 में 15 साल के वैभव ने 16 मैचों की 16 पारियों में 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाते हुए 776 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप जीता था। इस दौरान वैभव ने 72 छक्के लगाए, जो एक सीजन का रिकॉर्ड है।

सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा दल लौटा, रायपुर रेलवे स्टेशन पर 1040 विशिष्टजनों का हुआ आत्मीय एवं भव्य स्वागत

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संस्कृति, आस्था और राष्ट्रीय एकात्मता का अनूठा अभियान हुआ सफल

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय स्वाभिमान और आध्यात्मिक चेतना को नई ऊर्जा देने वाली छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी ''सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा'' आज सफलता के साथ संपन्न हुई। पांच दिवसीय इस ऐतिहासिक यात्रा के बाद प्रदेश के सभी जिलों से शामिल 1040 विशिष्टजन सकुशल रायपुर लौटे, जहां रायपुर रेलवे स्टेशन पर उनका आत्मीय, गरिमामय एवं भव्य स्वागत किया गया। यात्रियों के चेहरों पर संतोष, श्रद्धा और आत्मिक आनंद की झलक इस अभिनव यात्रा की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण बनी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित इस विशेष सांस्कृतिक यात्रा ने केवल श्रद्धालुओं को भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन का अवसर ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपरा और राष्ट्रीय एकात्मता का भी जीवंत अनुभव कराया। यात्रा ने यह संदेश भी दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव को भी समान प्राथमिकता दे रही है। इस यात्रा में प्रदेश के पद्मश्री सम्मान प्राप्त विभूतियों, राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान से सम्मानित कलाकारों, साहित्यकारों, संस्कृति कर्मियों, समाजसेवियों तथा अन्य विशिष्टजनों ने सहभागिता की। इससे छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, कला, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ के सुव्यवस्थित प्रबंधन में आयोजित इस यात्रा की देशभर में सराहना हुई। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग, गुजरात राज्य सरकार के समन्वय तथा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के आत्मीय सहयोग से यात्रा का प्रत्येक चरण अत्यंत सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान सोमनाथ के दिव्य दर्शन-पूजन के साथ मंदिर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक

विरासत का अवलोकन किया। प्रतिभागियों ने भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ धाम के महत्व को निकट से अनुभव किया। अनेक प्रतिभागियों ने अपने क्षेत्रों की पावन मिट्टी और नदियों का जल भगवान सोमनाथ को अर्पित कर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय एकता के सूत्र से जोड़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास पर आधारित आकर्षक लाइट एंड साउंड शो का भी अवलोकन किया, जिसने मंदिर के पुनर्निर्माण, भारतीय सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रेरक गाथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।पूरी यात्रा के दौरान आवागमन, आवास, भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा तथा अन्य सभी व्यवस्थाएं उच्च स्तर पर सुनिश्चित की गईं। संस्कृति एवं राजभाषा विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे स्वयं विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ पूरी यात्रा में उपस्थित रहे और प्रत्येक यात्री की सुविधा का विशेष ध्यान रखा। यात्रियों ने व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि शासन ने उन्हें परिवार जैसा स्नेह और सम्मान प्रदान किया। यात्रा से लौटे प्रतिभागियों ने इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताते हुए कहा कि वर्षों से संजोई गई सोमनाथ दर्शन की उनकी इच्छा शासन की इस निःशुल्क और सुव्यवस्थित पहल से पूरी हो सकी। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ के दिव्य दर्शन, वहां का आध्यात्मिक वातावरण, ऐतिहासिक लाइट एंड साउंड शो तथा उत्कृष्ट यात्रा प्रबंधन ने उन्हें आत्मिक शांति के साथ भारतीय संस्कृति के प्रति नया गर्व प्रदान किया। रायपुर रेलवे स्टेशन पर लौटे श्रद्धालुओं का पारंपरिक रीति-रिवाज, पुष्पवर्षा, माल्यार्पण और आत्मीय अभिनंदन के साथ भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के दौरान यात्रियों ने छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा केवल तीर्थाटन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का प्रेरक अभियान रही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच के अनुरूप यह यात्रा इस बात का प्रमाण बनी कि छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर से जन-जन को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में संस्कृति विभाग द्वारा किए गए सफल आयोजन ने यह भी सिद्ध किया कि इस तरह के आयोजन समाज में आत्मगौरव, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा की सफलता ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिदृश्य में नई पहचान प्रदान की है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, गुजरात राज्य सरकार, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट तथा छत्तीसगढ़ शासन के समन्वित प्रयासों से संपन्न यह ऐतिहासिक यात्रा आने वाले समय में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय एकात्मता के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में याद की जाएगी।

सेवा सेतु बना ग्रामीणों का भरोसेमंद डिजिटल सहारा

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। जिला प्रशासन बीजापुर की डिजिटल पहल सेवा सेतु ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए सुशासन का प्रभावी माध्यम बन रही है। सेवा सेतु केन्द्रों के माध्यम से अब नागरिकों को विभिन्न शासकीय प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल रही हैं। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बच रहे हैं तथा शासन के प्रति उनका विश्वास भी मजबूत हो रहा है। विकासखंड भैरमगढ़ की ग्राम पंचायत तड़केल निवासी वंदना हेमला ने सेवा सेतु केन्द्र नेलेसनार के माध्यम से स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया। आवेदन प्राप्त होने के बाद उसी दिन उनका आवेदन निराकृत कर स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया।

सेवा सेतु केन्द्र के प्रबंधक श्री मुकेश कुमार बघेल ने उन्हें प्रमाण-पत्र प्रदान किया। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध रही, जिससे उन्हें किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े।वंदना हेमला ने बताया कि पहले किसी भी शासकीय प्रमाण-पत्र के लिए कई बार कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों खर्च होते थे।

पशुधन विकास विभाग की योजना से बदली सदाशिव कुरगुड़ की जिंदगी किसान क्रेडिट कार्ड से मिला 30 हजार रुपए का ऋण

मुर्गी पालन से हर वर्ष 80 हजार रुपये का शुद्ध लाभ

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बीजापुर जिले के भोपालपटनम विकासखंड के ग्राम उल्लूर निवासी सदाशिव कुरगुड़ इसकी प्रेरणादायक मिसाल हैं। उन्होंने पशुधन विकास विभाग की किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू किया और आज अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर चुके हैं।

पशुधन विकास विभाग की योजना से बदली सदाशिव कुरगुड़ की जिंदगी

योजना से मिला स्वरोजगार का अवसर

सदाशिव कुरगुड़ कृषि कार्य के साथ अतिरिक्त आय का स्रोत विकसित करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी उनके सामने बड़ी चुनौती थी। इसी दौरान उन्हें पशुधन विकास विभाग की किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी मिली। विभाग के मार्गदर्शन से उन्हें बैंक के माध्यम से 30 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ।इस राशि से उन्होंने मुर्गी पालन के लिए चूजे खरीदे और उनके पालन-पोषण के लिए आवश्यक आहार एवं अन्य व्यवस्थाएं कीं।

तकनीकी मार्गदर्शन से मिली सफलता

पशुधन विकास विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन, नियमित देखभाल और बेहतर प्रबंधन के कारण उनका मुर्गी पालन व्यवसाय लगातार आगे बढ़ता गया। आज वे इस व्यवसाय से प्रतिवर्ष लगभग एक लाख रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं, जिसमें करीब 80 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है।

इस अतिरिक्त आय से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है और वे आत्मनिर्भर जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

अब बड़ा पोल्ट्री फार्म स्थापित करने का सपना

सदाशिव कुरगुड़ बताते हैं कि पशुधन विकास विभाग की योजना ने उन्हें आत्मविश्वास और रोजगार दोनों दिए हैं। अब उनका लक्ष्य भविष्य में एक आधुनिक व्यावसायिक पोल्ट्री फार्म स्थापित कर रोजगार का दायरा बढ़ाना है।

उन्होंने पशुधन विकास विभाग और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि अधिक से अधिक ग्रामीण और युवा इन योजनाओं का लाभ लें, तो वे भी स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकते हैं।

ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बना रही हैं विभागीय योजनाएं

पशुधन विकास विभाग की विभिन्न योजनाएं जिले में किसानों और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, उनकी आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही हैं। सदाशिव कुरगुड़ की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर कोई भी किसान अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

खरीफ सीजन 2026 : सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। खरीफ सीजन 2026 के मद्देनजर सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिले की समस्त सेवा सहकारी समितियों में किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद और प्रमाणित बीज का भंडारण सुनिश्चित कर लिया गया है। उप संचालक कृषि ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे ऐन वक्त पर होने वाली भारी भीड़भाड़ से बचने और समय पर बोनी का कार्य संपन्न करने के लिए अपने विकासखंड की निकटतम सहकारी समिति से अनुशंसित मात्रा में खाद एवं बीज का शीघ्र उठाव कर लें। किसानों को खाद और बीज प्राप्त करने के लिए अपने साथ आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है। साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए किसान भाई अपनी संबंधित सहकारी समिति अथवा कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

जिले में कृषि विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का व्यापक और व्यवस्थित भंडारण किया गया है। वर्तमान में जिले के तीनों विकासखंडों में कुल 6141.954 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, जिसमें सारंगढ़ में 2572.179 मीट्रिक टन, बरमकेला में 2256.130 मीट्रिक टन और बिलाईगढ़ में 1313.645 मीट्रिक टन का स्टॉक शामिल है। इसी प्रकार, फसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले सुपर फास्फेट की कुल उपलब्धता 1071.400 मीट्रिक टन है, जिसमें सारंगढ़ को 439.450 मीट्रिक टन, बरमकेला को 498.400 मीट्रिक टन और बिलाईगढ़ को 133.550 मीट्रिक टन आबंटित किया गया है। डीएपी खाद की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक है और समितियों में कुल 487.740 मीट्रिक टन डीएपी सुरक्षित रखा गया है, जिसमें सारंगढ़ में 307.650 मीट्रिक टन, बरमकेला में 123.190 मीट्रिक टन तथा बिलाईगढ़ में 56.900 मीट्रिक टन का भंडारण है।

नशा मुक्त भारत अभियान को मिला जनसहभागिता का संबल

जिला जेल में बंदियों ने ली नशामुक्त जीवन की शपथ, गीत-संगीत से दिया जागरूकता का संदेश

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन तथा छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में नशामुक्त भारत सप्ताह और नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी विरोधी सप्ताह पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के समापन पर जिला जेल रायगढ़ में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम हुआ। यहां बंदियों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन अपनाने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में सभी बंदियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम, उनके सामाजिक-परिवारिक प्रभाव और स्वस्थ जीवनशैली के फायदे बताए गए। गीत-संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए भी नशामुक्ति का प्रभावी संदेश दिया गया, जिसे सभी ने सराहा। उपसंचालक समाज कल्याण रायगढ ने कहा कि नशा व्यक्ति की क्षमता, परिवार की खुशहाली और समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। युवाओं को नशे से बचाने और समाज में जागरूकता लाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।उन्होंने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, उपचार- पुनर्वास सेवाओं से जोड़ना और जनसहभागिता से नशामुक्त भारत बनाना है। विभाग ने आमजन से अपील की कि वे खुद नशे से दूर रहें और परिवार-मित्रों को भी नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करें।

नई सोच, नई तकनीक और नई उम्मीद:नैनो उर्वरकों से सशक्त हो रही खेती

कृषक रतन सिंह ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया अपनाकर आधुनिक खेती की दिशा में बढ़ाया कदम

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में नैनो उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कोरबा जिले के ग्राम जपेली निवासी कृषक श्री रतन सिंह इसका एक प्रेरक उदाहरण हैं। लगभग साढ़े चार एकड़ कृषि भूमि पर खेती करने वाले श्री रतन सिंह के लिए कृषि ही आय का प्रमुख साधन है। वर्षों से खेती कर रहे रतन सिंह ने बदलते समय के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का निर्णय लिया और पिछले वर्ष से अपने खेतों में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया का उपयोग शुरू किया। श्री रतन सिंह बताते हैं कि प्रारंभ में उन्होंने नैनो उर्वरकों को लेकर जानकारी प्राप्त की और कृषि

विभाग के मार्गदर्शन में इसका उपयोग किया। उपयोग के बाद उन्हें फसलों की वृद्धि एवं विकास में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। उनका कहना है कि नैनो उर्वरक कम मात्रा में उपयोग होने के बावजूद प्रभावी साबित हो रहे हैं, जिससे खेती के कार्यों को अधिक व्यवस्थित ढंग से करने में सहायता मिल रही है। उन्होंने बताया कि नैनो उर्वरकों के उपयोग से खेतों में पोषक तत्वों का बेहतर प्रबंधन संभव हुआ है। साथ ही इनके परिवहन, भंडारण एवं उपयोग में भी सुविधा मिलती है। आधुनिक तकनीक को अपनाने से खेती के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हुआ है तथा वे अन्य किसानों को भी नई कृषि तकनीकों की जानकारी लेने और उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

नैनो उर्वरक के प्रयोग से युवा किसान पुनम की खेती बनी लाभकारी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। कोंडागांव जिले के ग्राम ग्राम दावड़ीबेड़ा (चिखलपुटी) के युवा किसान पुनम नेताम आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी बना रहे हैं। उन्होंने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग कर अपनी फसलों में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया है। पिछले दो वर्षों से वे धान, मक्का और सब्जियों की खेती में नैनो उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पुनम नेताम ने बताया कि गत वर्ष उन्होंने 10 एकड़ भूमि में मक्का की खेती की थी। नैनो उर्वरकों के उपयोग से फसल की वृद्धि अच्छी हुई और उत्पादन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। उनका कहना है कि नैनो उर्वरक का छिड़काव सीधे पौधों की पत्तियों पर किया जाता है, जिससे पोषक तत्व शीघ्रता से पौधों तक पहुंचते हैं। इससे उर्वरक की उपयोग क्षमता बढ़ती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत, पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से समय के साथ मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। पुनम ने बताया कि आधुनिक तकनीक को अपनाकर खेती की लागत कम हुई है और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है।

हिट एंड रन मुआवजा योजना के संबंध में बैठक आयोजित

मुआवजा प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की गई चर्चा

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सुप्रीम कोर्ट के एस. राजसीकरण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण में 12 जनवरी 2024 को पारित आदेश तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय परिसर में हिट एंड रन मुआवजा योजना-2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में अज्ञात वाहनों से प्रभावित मृतकों एवं गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को समयबद्ध मुआवजा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को निर्धारित मुआवजा समय पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज समयबद्ध ढंग से तैयार कर पुलिस एवं परिवहन विभाग के समन्वय से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, ताकि पात्र हितग्राहियों को बिना अनावश्यक विलंब के क्षतिपूर्ति मिल सके।

नक्सलमुक्त बस्तर के चहुंमुखी विकास के लिए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने समाज प्रमुखों से मांगा सहयोग

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा आज जिला पंचायत कांकेर सभाकक्ष में सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों की बैठक लेकर बस्तर के नक्सल उन्मूलन के बाद चहुंमुखी विकास, सामाजिक एकता तथा आदिवासियों की पारंपरिक संस्कृति और विरासत को सहेजने, संरक्षित करने पर चर्चा की। जिसमें जिले में पेसा एक्ट का समुचित क्रियान्वयन और पारंपरिक देव स्थलों को संरक्षित करने जैसे विषयों पर द्विपक्षीय सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान समाज प्रमुखों ने भी बारी बारी से सुझाव दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में समाज प्रमुखों से कहा कि किसी समाज की परंपरा और सांस्कृतिक धरोहरों व पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने में समाज

की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसी बड़े लक्ष्य की सफलता समाज के सहयोग से ही संभव होती है और बस्तर में नक्सल उन्मूलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र की मुख्यधारा से टूट कर हिंसा का मार्ग अपनाने वाले युवाओं को वापस मुख्यधारा में लेकर आने में समाज प्रमुखों ने सराहनीय कार्य किया, जिसमें सुरक्षा बलों और जवानों का सतत् सहयोग मिला, जिसके फलस्वरूप आज बस्तर का लाल आतंक से मुक्त होना संभव हुआ। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आज वर्षों से बंद मेला-मड़ई, बाजार, हाट अब आबाद होने लगे हैं। पहले जहां रिश्तेदार भी घर आने में डरते थे वे भी बेखौफ आने जाने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी वे पहली बार (नक्सलवाद से) आजाद होने का अनुभव कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि कतिपय बाहरी लोग स्थानीय लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि बस्तर के संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। इस पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि बस्तर का विकास बस्तर के युवाओं और लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय संसाधनों का प्रयोग कर ही ग्रामों का विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए शुरुआत के रूप में सुरक्षा कैम्पों को सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान द्वारा स्थानीय संसाधनों से ही विकसित किया जाएगा। समाज प्रमुखों से चर्चा के दौरान श्री शर्मा ने बताया कि इसी क्रम में अब बस्तर के देव स्थलों को संरक्षित करने के लिए 197 गांवों के देव स्थलों का राजस्व रिकॉर्ड में चिन्हांकन कर उसे स्थायी पंजीयन की व्यवस्था की जा रही है ताकि देव स्थलों को अच्छे से संरक्षित किया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा पेसा एक्ट को और भी सशक्त करने का कार्य किया गया है।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी
आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा